

per cent. With these words, I request the House to pass this Statutory Resolution.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): The question is:

That in pursuance of Sub-section (1) of section 8 of the Customs Tariff Act, 1975, read with sub-section (3) of section 7 of the said Act, this House hereby approves of Notification No.132/2000-Customs dated 17th October, 2000 (G.S.R.793 (E) dated 17th October, 2000) which seeks to amend the Second Schedule to the Customs Tariff Act so as to increase export duty leviable on hides, skins and leathers, tanned and untanned, all sorts, but not including manufactures of leathers falling under Heading No.14 of the said Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 from 25 per cent to 60 per cent."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Now, we will take up the Statutory Resolution and the National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Bill, 2000. Shri Pranab Mukherjee. Not here. Shri Suresh Pachouri. Not here. Shri Ramachandra Khuntia. Not here. So, the Statutory Resolution is not being moved.

THE NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL, 2000

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981, as passed by Lok Sabha be taken into consideration."

Sir, the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) was established under the provisions of NABARD Act, 1981 with a view to providing refinance to Cooperative Banks, Regional Rural Banks and Commercial Banks for promotion of agriculture, small-scale industries, cottage and village industry. On behalf of the RBI, it also carries out supervision of the RRBs, and the cooperative financial institutions.

[20 December, 2000] RAJYA SABHA

In order to provide greater operational flexibility to NABARD and take care of the changes that are taking place in the financial sector, certain amendments in the NABARD Act have become necessary. It is in this context that the present Amendment Bill is being moved. The salient features of the Bill are:-

- (i) To increase the capital of NABARD from Rs. 500 crores to Rs. 5000 crores.
- (ii) Changes are being made in the constitution of the Board of Directors. Representation of the State Governments is being increased as recommended by the Inter State Council.
- (iii) NABARD is being vested with sufficient flexibility in the matter of mobilization of resources.
- (iv) Section 19 of NABARD Act is being amended to authorise NABARD to float bonds with or without Government guarantee. The Government of India had to promulgate an Ordinance for this amendment so as to enable NABARD to take advantage of Capital Gains Bonds Scheme announced during the Union Budget for the current year.
- (v) Amendments are being made to enable NABARD to grant loans to the State Governments as well as direct loans for projects in exceptional circumstances.
- (vi) NABARD is also being enabled to set up subsidiaries as and when required.

It is essential that these amendments are carried out early, so that NABARD could embark upon the necessary organizational and operational changes required to more effectively focus on agriculture and rural development.

Sir, I request this august House to consider and pass the Bill.

The question was proposed

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने इस संबंध में संकल्प भी प्रस्तुत किया था और उसके पीछे कारण यह था कि 26 सितम्बर 2000 को जिस जल्दबाजी में इस बिल से संबंधित ऑर्डिनेंस जारी किया गया, वह असामयिक था। यद्यपि बिल में जिन बातों का प्रोव्हीजन किया गया है, मैं उन प्रावधानों का विरोध नहीं कर रहा हूँ लेकिन जिस मंशा से

जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, मुझे उस मंशा से आपत्ति थी और इसीलिए मैंने इसके लिए संकल्प भी प्रस्तुत किया था। इसके पीछे मेरी धारणा यह थी कि जो संसदीय परम्परा है और संसदीय आचरण है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जब सत्र चल रहा हो, तब इस प्रकार के निर्णय लिये जाने चाहिए जो किसानों से संबंधित हैं। मान्यवर, दरअसल जो नाबार्ड ऐक्ट 1981 है, उसके तहत नाबार्ड की स्थापना की गयी थी और उसके पीछे मंशा यह थी कि किसानों को अपना काम करते समय जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ऋण लेने में और ऋण को वापिस पटाने में जिन विसंगतियों का उसको सामना करना पड़ता है, उनका उसे सामना न करना पड़े। इसीलिए कृषि के विकास को ध्यान में रखते हुए छोटी-छोटी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए - खास करके जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, विलेज इंडस्ट्रीज हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का जो व्यवसाय है, उसको विकसित करने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए और विशेष रूप से जो ग्रामीण अंचल है, उनमें इन सब गतिविधियों के संचालन के लिए किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए उन्हें वित्तीय मदद नाबार्ड के जरिए मिल सके, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए नाबार्ड ऐक्ट, 1981 पास किया गया था और नाबार्ड की स्थापना की गई थी और उसी ऐक्ट में कुछ संशोधन करके इस बात को प्रस्तुत किया जा रहा है जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल, 2000 के स्वरूप में है।

मान्यवर, इसमें जो व्यवस्था की गई है, दरअसल मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि वह एक अच्छा कदम है लेकिन इसके अलावा कुछ और बातों का समावेश किया जाना जरूरी है। जब हम यह सोचकर चलते हैं कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, 70 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि व्यवसाय में हैं तो अगर हम भारत की बेहतरी चाहते हैं तो कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की बेहतरी करना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम यह देखें कि कृषि से संबंधित जो भी बातें हैं, उन पर हम लोग प्राथमिकता और वरीयता के आधार पर ध्यान दें। जब कृषकों को ऋण देने की बात आती है तो उसमें छोटे-छोटे बैंकों का इनवोल्वमेंट है, उसमें नाबार्ड बैंक की एक अहम भूमिका है। नाबार्ड बैंक के सही संचालन के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इसके रिसोर्सज बढ़ाएं और उन रिसोर्सज को न केवल बढ़ाएं बल्कि समुचित रिसोर्सज का हम प्रावधान नाबार्ड के सामने रखें, ऐसी व्यवस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को की जानी बहुत जरूरी है।

मान्यवर, जहां तक जी.एल.सी.1 और जी.एल.सी.2 का प्रश्न है, जो जनरल लाईन ऑफ क्रेडिट की बात है, वह पिछले तीन साल से रिजर्व बैंक ने बढ़ाना रोक दिया था, जिसके लिए अभी दिसम्बर माह में उन्होंने 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। इस बिल में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, उसमें जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, वह 500 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 5000 करोड़ रुपए तक करने का प्रावधान है और इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो ओनरशिप है, वह 51 परसेंट गवर्नमेंट की रहेगी जिसमें आर.बी.आई. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शामिल हैं और 49 परसेंट प्राइवेट शेयर होल्डर्स रहेंगे। जहां तक इस कदम का प्रश्न है, मैं सोचता हूँ कि यह एक सामयिक कदम है। इससे निश्चित रूप से किसी न किसी ढंग से सरकार का एक अंकुश भी रहेगा और अगर कहीं कोई विसंगति होती है तो उस विसंगति को दूर करने का सरकार उस अंकुश की वजह से कहीं न कहीं उपयोग भी कर सकेगी।

जहां तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रश्न है, इसमें जो राज्य सरकार से पहले प्रतिनिधि होते थे, वे दो हुआ करते थे तो उनको बढ़ा दिया गया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की

संख्या बढ़ाकर 15 से 19 कर दी गई है। इससे मुझे लगता है कि राज्य सरकार का भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में say रहेगा, सीधे यहाँ से कोई कार्य संचालन नहीं होगा। मैं सोचता हूँ कि यह भी एक अच्छा कदम है क्योंकि होता क्या है कि नाबार्ड के जरिए जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं, आर.आर.बी. हैं, उनको लोन दिया जाता है। अब यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकारों को भी लोन दिया जाता है। राज्य सरकारें अलग-अलग मद में नाबार्ड के जरिए लोन लिया करती हैं चाहे वॉटर फैसिलिटीज देने की बात हो, चाहे रोड सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे स्कूलों की मरम्मत करने की बात हो, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात हो। राज्य सरकारों के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स के संचालन के लिए राज्य सरकारें नाबार्ड से लोन लेती हैं और फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो निश्चित रूप से जब यह बिल पास होगा तो इस बिल के पास होने से जो राज्य सरकारों के प्रतिनिधि बढ़ाने का इसमें समावेश किया गया है, मैं सोचता हूँ कि वह एक अच्छा कदम है लेकिन वहाँ पर दूसरी ओर राज्य सरकारें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स रिकमंड करके भेजती हैं जिनमें कि उनकी खुद की विलचस्पी होती है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा यह अनुभव रहा है कि मान लीजिए कोई सिंचाई मंत्री किसी खास निर्वाचन क्षेत्र का है। सिंचाई मंत्री द्वारा जब इरिगेशन फैसिलिटी देने की बात होती है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स तैयार करने की बात होती है, उसके तहत ऋण देने की बात होती है तो केवल उस क्षेत्र के लिए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स रिकमंड करके वह सरकार भेजती है जबकि किसी और क्षेत्र के लिए, जो उसी राज्य में होते हैं, जहाँ सिंचित सुविधाएं ज्यादा प्रदान करने की बात होती है तो उसके लिए नहीं हो पाता है। लेकिन अब इस बिल के जरिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि केवल राज्य सरकारों पर ही आश्रित न रहा जाए। यद्यपि राज्य सरकारों के प्रतिनिधि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो बढ़ जाएंगे लेकिन वे राज्य सरकारों पर ही आश्रित न रहेंगे बल्कि यह बोर्ड एक इंडिपेंडेंट डिस्ीजन ले ले। जिस बोर्ड के गठन का प्रावधान इस बिल में किया गया है मैं सोचता हूँ कि यह भी एक सामयिक और उचित कदम है।

इसमें डायरेक्ट लैंडिंग की भी व्यवस्था की गई जो पहले नहीं थी। जब विदेशों के प्रोजेक्ट्स की बात आती है, उसने फॉरेन करेसी मिलने की बात होती है, उसमें रुबल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विदेशों से जब ऋण लेने की बात आती है तो उस संबंध में मान्यवर कहना चाहता हूँ - क्योंकि हमारा ऐसा तजुर्बा रहा है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे वाटर शेड डेवलपमेंट की बात होती है, इसकी सदन में बहुत गंभीर चर्चा भी होती आई है कि हिंदुस्तान के कई क्षेत्रों में वाटर लेवल कम हो रहा है और इस वाटर लेवल के कम होने की वजह से लोगो को पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है, पशुओं को भी पानी की जो आवश्यकता होती है वह पूरी नहीं हो रही है, इसके अलावा और भी जिन भदों में पानी की आवश्यकता होती है जैसे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए या अन्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए, वह भी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए एक वाटर शेड प्रोग्राम चला था और इस प्रोग्राम के लिए बहुत से फॉरेन एडिड प्रोजेक्ट्स भी हैं लेकिन ये प्रोजेक्ट्स तभी चल पाएंगे जब उनमें इस प्रकार की व्यवस्था का समावेश होगा। अब जबकि इस बिल में उस प्रकार की व्यवस्था का भी समावेश है तो मैं समझता हूँ कि यह अच्छा कदम है।

इसमें कन्सल्टेंट सर्विस की बात भी है। आज हम एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रयोग की बात करते हैं, बायो टेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर फील्ड में प्रयोग की बात करते हैं लेकिन यह तभी हो पाएगा जब हम इन सुविधा में इस चीज का प्रोविजन रखें और इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए जो फॉरेन एडिड प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें नाबार्ड के जरिए

मदद मिल जाएगी और नाबार्ड अलग-अलग स्थानों पर, उन क्षेत्रों में जहाँ इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स चलाने की आवश्यकता है अपना पैसा लगा पाएगी। इस बिल में इस चीज का जो समावेश किया गया है उसका भी लाभ किसानों को मिल पाएगा। जब मैंने अपनी बात प्रारंभ की थी तो यह कहा था कि यदि देश की प्रगति और विकास के द्वार पर दरतक देनी है, यदि देश की उन्नति की बात करनी है तो आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जो बहुसंख्यक लोग हैं, कृषि व्यवसाय पर आधारित सत्तर प्रतिशत से भी ज्यादा लोग हैं उनकी बेहतरी और विकास के बारे में हम विचार करें। मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि नाबार्ड का रि फाइनेंस का शेयर दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है। यह 1995-95 में 30 % था, 1996-97 में घटकर 29 % रह गया और 1997-98 में घटकर 27 % रह गया और जब हम आज की चर्चा करते हैं तो स्थिति यह है कि वह घटकर 24% हो गया है। जब हम नाबार्ड के रि फाइनेंस के घटने की बात करते हैं और जो इसकी वजह मजूर आती है तो वह है GLC, जिसका हमने जिक्र किया। GLC-1 और GLC-2 की वजह से रि फाइनेंस कम हो रहा है। आज इसके बारे में विचार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

एक अन्य बात मैं एन.आर.सी. फंड के बारे में कहना चाहूंगा, जिसका उल्लेख इस बिल में किया गया है कि जो नेशनल रूरल क्रेडिट फंड है उसके बारे में भी हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो कमी इस बिल में रह गई है उसकी तरफ मंत्री जी जो ध्यान देना पड़ेगा कि इस एन.आर.सी. फंड के अंतर्गत जो राशि दी गई थी वह पिछले काफी समय से रोक दी गई है। मान्यवर, पहले यह आठ सौ से एक हजार करोड़ रुपया दिया जाता था। लेकिन अब जो व्यवस्था हुई है उस व्यवस्था के अन्तर्गत इसे घटाकर एक करोड़ तक कर दिया है। मान्यवर, मंत्री जी इस बारे में जब अपना उत्तर दे तो मैं समझता हूँ कि वे इस बारे में गंभीरता से ध्यान देंगे, ऐसा मेरा आपके माध्यम से आग्रह है। जब हम कार्स्टली फंड लेंगे तो मान्यवर जो कार्स्ट आफ फंड होता है वह भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए जब हम प्राइवेट मार्केट से बौरी करते हैं तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया से पर्याप्त राशि नाबार्ड को नहीं मिल पाएगी इसलिए वह बाहर से प्राइवेटली बौरींग करेगा। निश्चित रूप से जब वह किसानों को ऋण देगे तो वह ज्यादा उनसे ब्याज वसूल करेगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है चाहे एनआरसी फंड के अन्तर्गत और चाहे दूसरे फंड के अन्तर्गत जो सुविधा मिलनी चाहिए वह सुविधा उनको प्राथमिकता के आधार पर दी जानी चाहिए।

मैं अपनी बात खत्म करूँ इससे पहले मैं दो-तीन और बातें कहना चाहता हूँ। मान्यवर, जो नाबार्ड है वह पूरा का पूरा रिजर्व बैंक आफ इंडिया पर निर्भर है। इसके लिए जरूरी यह है कि इसकी जो रि फाइनेंस की स्कीम है उसके सुधार पर हम लोगों को विचार करने की जरूरत है।

मान्यवर, इसी तरह से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड है उसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। जब मैं एडवांस टेक्नालाजी के उपयोग का जिक्र कर रहा हूँ तो यह तभी संभव हो पाएगा, जब आर एंड डी के लिए हम जो ग्रांट रखते हैं उसको बढ़ाने का प्रोविजन किया जाए। नाबार्ड ऐक्ट 1981 के सेक्शन 44 में इसका प्रोविजन है। इसलिए सेक्शन 44 पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो आर एंड डी फंड है उसमें उसकी ग्रांट को बढ़ाया जाना चाहिए। यह 21.77 करोड़ ही 31 मार्च, 2000 तक रहा है। इसमें बढ़ोतरी की जरूरत है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। जब हम बात करते हैं ड्रिप इरीगेशन प्रोजेक्ट की, जब हम बात करते हैं स्प्रिंकलर इरीगेशन की फेसिलिटी किसानों को देनी चाहिए, तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि

आज भी हमारे देश में 67 प्रतिशत किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाती है। उनको सिंचाई की सुविधा मिल इससे लिए बहुत जरूरी है कि आर एंड डी पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसान तभी खुश रहेगा जब हम किसानों को सिंचाई की सुविधा का उपयोग करते हुए पायेंगे।

आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जो लाइफ इश्योर्स कारपोरेशन है उसका सोशल डेवलपमेंट के लिए जो कमिटमेंट है उस पर वह लोग जोर देते हैं। लेकिन नाबार्ड के जरिए जो ऋण देने की बात है वह सोशल डेवलपमेंट पर भी कुछ ध्यान दे पाए तभी हम उस कैटेगरी के लोगों के अपलिफ्ट की बात कर पायेंगे जो कि सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनको हम दलित कहते हैं, जिनको हम नग्लेक्टेड क्लास के लोग कहते हैं उनके लिए हम विचार कर पायेंगे। नाबार्ड ने फिलहाल इस बिल में प्राविजन रखा कि बिचौलियों को इससे अलग रखा जाएगा। मैं सोचता हूँ कि यह जो प्रावधान हमने अभी डिस्कस किया, एनएचएआई में बीच में जो बिचौलियों का प्रावधान है यह उससे हटकर है और मैं सोचता हूँ इससे किसानों को सीधी मदद मिल पाएगी। लेकिन इस सब के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम केवल राज्य सरकारों पर आश्रित न हों। एक नाबार्ड की मानीटरिंग की भी स्कीम होनी चाहिए, मानीटरिंग की व्यवस्था पेपर में है। इस बिल में है कि जिन प्रोजेक्ट के लिए नाबार्ड के जरिए ऋण की सुविधाएँ दी जायेंगी उनका मानीटरिंग नाबार्ड करेगा। लेकिन हम जो फीड बैक लेते हैं वह राज्य सरकारों से लेते हैं। मान्यवर, मैं गांवों से जुड़ा हुआ हूँ। गांवों में लोगों की मांग यह रहती है कि जो रोड बननी है वह नाबार्ड को रोड बननी चाहिए। इसके पीछे भावना, आशय यह रहता है कि नाबार्ड से ऋण भी मिल जाएगा और नाबार्ड से जिस रोड के निर्माण के लिए पैसा मिलेगा वह रोड पक्की और अच्छी बनेगी। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह पाएगी। इसके पीछे भावना यह रहती है। तो मानीटरिंग सही होना बहुत आवश्यक है। इस बिल पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो नाबार्ड को यह निर्देश देना आवश्यक है कि वह मानीटरिंग ऐसी करे कि यदि कहीं कमी रह पाए तो मानीटरिंग के जरिए उस ऋण को भी वापस ले सके ताकि विश्वसनीयता नाबार्ड की बनी रही। उसकी वह विश्वसनीयता कायम रहे। यद्यपि बात यह आ सकती है कि जो ऋण हमें नाबार्ड देता है ज्यादा परसेटज का ब्याज लेता है। इसमें कमी आना जरूरी है। लेकिन यह तब संभव हो पाएगा जब रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से जो इस नाबार्ड को फाइनेंस करने के लिए सहयोग मिलना चाहिये, वह समुचित सहयोग मिल पाए। मुझे विश्वास है कि आज जब हम सब लोग इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं तो इस बिल पर चर्चा करते समय हम इस नतीजे पर भी पहुंच पायेंगे कि नाबार्ड जिन उद्देश्यों को सामने रख कर स्थापित किया गया था, जिस 1981 के एक्ट का संशोधन करने के लिए, बहस करने के लिए हम बैठे हैं तो निश्चित रूप से नाबार्ड को हम सारा सहयोग प्रदान करते हुए वह अधिकार भी प्रदान करेंगे जिससे उस मंशा की पूर्ति हो सके जिस मंशा को सामने रखते हुए नाबार्ड का गठन किया गया था। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री अधिक शिरोडकर) : धन्यवाद पचौरी जी। श्री संघ प्रिय गौतम जी।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से इस विधेयक का समर्थन करूंगा और समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। लेकिन पृष्ठभूमि में एक दो शंकाएँ हैं, इसलिए मैं उनका समाधान चाहूंगा। हमारे देश में बैंकों की प्रणाली बहुत पुरानी है और देश में बहुत बैंक थे लेकिन ज्यादातर शाखाएँ शहरों में थी। बैंकों की शाखाएँ देहातों में नहीं थी। जब कृषि का विकास हुआ और ग्रामीण विकास की ओर सरकार की निगाहें गई तो फिर ग्रामीण क्षेत्र

को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए ग्रामीण बैंकों की भी आवश्यकता पड़ी और तब ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक खोले गये, बैंकों की शाखाएं खोली गईं। इन बैंकों को पैसा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना की भी आवश्यकता पड़ी और इस बैंक की स्थापना हुई। इस विधेयक का उद्देश्य बहुत अच्छा है। आप कहते हैं कि पहले विधेयक में कुछ कमियां थी, उनको दूर करना है। दूसरा यह है कि बैंकों को स्वाधिकार हो अपने कार्यों के कार्यान्वयन में, इसलिए भी संशोधन करना पड़ा। काम करने में लचीलापन हो, इसलिए भी संशोधन कर रहे हैं। बैंकों के काम का दायरा भी बढ़ जाए इसलिए भी संशोधन कर रहे हैं। बैंक संसाधन जुटा सकें इसलिए भी संशोधन कर रहे हैं। सब से बड़ी बात यह है कि जो केन्द्र सरकार से इन बैंकों के संचालन में बोर्ड के निदेशक हैं, उनके मामले में हस्तक्षेप केन्द्र सरकार का था वह हस्तक्षेप कम हो जाए या जो बैंक के निदेशक हैं वह काम बगैर किसी रोक-टोक के आसानी से काम कर सकें, इसलिए भी संशोधन कर रहे हैं। खास तौर से आज जो आर्थिक परिदृश्य बन गया है सारे विश्व में उसको दृष्टिगत रखते हुए हमें यह संशोधन करना पड़ा है। लेकिन विशेष बात यह है कि इसकी पूंजी सीमा 500 करोड़ रुपये निर्धारित कर दी गई थी लेकिन अब उसको बढ़ा कर के 5000 करोड़ कर दिया गया है। यह एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम है और ग्रामीण विकास की दिशा में इससे सहयोग मिलेगा। मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन मान्यवर, मुझे देख कर कभी कभी हंसी भी आती है कि लोक सभा में यह बिल बिना किसी बहस के पास हो गया। हमारे पचीसी जी ने भी कहा कि मैं गांव में रहता हूं। आप इसके उद्देश्यों को देखिये। उद्देश्यों में कहा है :

"The National Bank for Agriculture and Rural Development is an apex development bank in the field of agriculture and rural development."

यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए है। दूसरा आगे बहुत सी बातें कहते हुए यह कहा गया :

...to effectively serve the agricultural and rural sector...

यह आंबेडकर से कहा गया और फिर कहा गया :

"...long title of the Act is proposed to be amended to highlight the nature and status of the National Bank for Agriculture and Rural Development as a development bank..."

यह डवलपमेंट बैंक ग्रामीण विकास और कृषि के लिए है लेकिन इसमें कितनी भागीदारी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगो की है, मुझे यह देख कर बहुत अफसोस हुआ। मैं चाहूंगा मेरी जी मेरी शंका का समाधान करेंगे। मान्यवर, जो वर्तमान विधेयक है, इसमें कहा गया :

Sir, clause 5 of the Bill is about amendment of section 6. It says:

"The Board of Directors of the National Bank shall consist of the following, namely:-

(a) Chairman;

(b) three directors from amongst experts in rural economics, rural development, village and cottage industries, small-scale industries or persons having experience in the working of co-operative banks, regional rural banks or commercial banks or any other matter the special knowledge or professional experience in which is considered by the Central Government as useful to the National Bank; Clause 5(1) (c) says, "Three directors from out of the directors of the Reserve Bank.

Further in clause 5(1) (e), it says, "Four directors from amongst the officials of the State Governments.

Then, Clause 5(1)(f) says, "Such number of directors elected in the prescribed manner, by shareholders other than the Reserve Bank..."

There is no director from the agricultural sector. There is no director from the unorganised agricultural labour.

क्योंकि एग्रीकल्चर की परिभाषा हमने की है। कृषि की परिभाषा क्या है? हो सकता है मैं गलत हूँ। I will stand corrected। मंत्री जी मुझे माफ करेंगे कि जिस उद्देश्य के लिए बैंक बनाया गया है उस क्षेत्र का कोई निर्देशक इसमें नहीं होगा - कृषि का और कृषि में काम करने वालों का। अभी कह रहे हैं कि 70 परसेंट लोग खेती में काम करते हैं। तो उनके हित को कौन देखेगा?

आगे एक और बड़ी हास्यास्पद बात आ गयी है इसमें। मंत्री जी का मैं ध्यान चाहूंगा :

"Provided that until the assumption of charge by the elected directors under this clause, the Central Government may at any time nominate such number of directors not exceeding four from amongst persons having special knowledge of, and professional experience in, agricultural science, technology, economics, banking, co-operatives, law, rural finance, etc."

इसमें भी एग्रीकल्चर साइंस का नाम है नाट एग्रीकल्चर। एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरिस्ट एग्रीकल्चर पदकर आया। वह किसान को, गंवार को शिक्षा देने लगा जो हल चला रहा था। उसने पूछा तू हल चलाकर दिखा दे और तू सीधी हरेया ला दे। वह नहीं जानता। तो प्रेक्टिकल, व्यावहारिक ज्ञान उसी को है जो खेती में काम करता है। खेती में काम करता है खेत मजदूर, खेती में काम करता है किसान। उसका प्रतिनिधित्व कहां इस बैंक के डायरेक्टर्स में है, तो उसका हित कहां संरक्षित है? फिर इसमें भी ताज्जुब की बात यह है कि ये कब तक हैं Until the

assumption of charge by the elected directors. ये कब लिए जाएंगे? अगर चार्ज ले लिया इलेक्ट्रेड डायरेक्टर्स ने तो फिर क्या होगा? तो नही लिए जाएंगे। अगर फिर ले लिया तो इनका क्या होगा? इसके बारे में साइलेस है। स्पष्टीकरण होना चाहिए कि ये कटीन्यू करेंगे या निकाल दिए जाएंगे। इस बात का स्पष्टीकरण मान्यवर इसमें होना चाहिए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब लोग जानते हैं - उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। बहुत पुरानी बात है। हमारा कृषि पर आधारित उद्योग ही हमेशा विश्व में हमारे व्यापार का आधार रहा है। आज भी तमाम सब चीजें हम खेती से प्राप्त करते हैं वहाँ धारा हो, ईंधन हो, साग सब्जी हो, खाद्यान्न हो, फल फूल हो, मेय हो - कोई भी चीज हो वहाँ एनीमल हसबैंड्री हो। मैं आपसे बता रहा था, अर्ज कर रहा था कि खेती की परिभाषा क्या है। खेती की परिभाषा - हार्टाकल्चर, एनीमल हसबैंड्री, फारेस्ट्री, डेयरी, पोल्ट्री एण्ड फिशरी कल्चर है। अब जो लोग ये काम करते हैं, ये गांव में रहने वाले काम करते हैं। उनको पैसा कौन देगा? ग्रामीण बैंक, और अब सारे बैंक हो गए कामर्शियल बैंक। यह भी बात आ गयी कि पैसा मिलता नहीं। इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड बांटने की बात आई, वरना यह बात ही क्यों आती। तो गांव में रहने वाले लोगों को पैसा मिले, ग्रामीण बैंकों की शाखाएं ज्यादा खुले और इस बैंक में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भागीदारी हो - नीति निर्धारण में, पैसा बांटने में इसलिए उनके प्रतिनिधियों का भी होना अति आवश्यक है। मुझे एक बात और कहनी है, एक मेरा शक और है। आगे आपने इसके सैक्शन में कहा है :Section 30 says: "The National Bank may, in exceptional circumstances to be recorded in writing by the Board, by itself or in association with other financial institutions or scheduled banks, make loans and advances, otherwise than by way of refinance to any person or class of persons or body corporate, on such terms and conditions, including security and repayable within such period not exceeding twenty-five years. अब ऐसा पैसा बैंक का सारा डिफाईंड नहीं है। बहुत से पर्सन डिफाईंडर होते हैं। यह पांच हजार करोड़ रुपये में से 25 साल की मियाद तक अगर ऐसे लोगों को पैसा उधार दे दिया गया तो फिर ग्रामीण विकास के लिए पैसा कहां से आयेगा? इसमें सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम इतनी धनराशि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक होगी। बहुत से लोग पैसा ले लेते हैं लेकिन वापस नहीं देते हैं। मंत्री जी की नयत तो अच्छी है और उद्देश्य भी अच्छा है, जिसके लिए यह विधेयक लाया गया है, राशि 500 करोड़ से 5000 करोड़ बनाई गई है, केन्द्र सरकार की दखल अंदाजी कम की जा रही है और आज के युग में उसको सामर्थ्य बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन शंका की कोई गुंजाइश छोड़नी नहीं चाहिए। हमारे देश में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वे वास्तव में आज भी पिछड़े हुए हैं। वहाँ पीने का पानी नहीं है, सड़के नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, राशनगार नहीं हैं, लोगों के पास काम नहीं है, राजगार नहीं है और बड़ी तादाद में गांवों के लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं, इसी कारण कि उनके वहाँ पर काम नहीं है। अगर बैंकों से पैसा मिलेगा तो उन्हें काम मिलेगा और शहरों को पलायन भी रुकेगा। इसके बाद जब शहरों को पलायन रुकेगा तो फिर शहरों पर आबादी का बोझ भी नहीं पड़ेगा। इसलिए माननीय मंत्री जी से यह आशा रखते हुए कि हो सकता है कि मेरी समझ में ही कमी हो, छोटी बुद्धि का व्यक्ति हूँ, तो मुझे दुरुस्त कर देंगे, अन्यथा इन शंकाओं का समाधान करेंगे।

इसके साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN (Kerala): Thank you, Madam Deputy Chairperson, my hon. colleagues have made their points on this Bill regarding NABARD. I would also like to raise some of our apprehensions regarding this Bill.

At the outset, I would say, NABARD had done a commendable work on rural infrastructure development, and also in assisting the agricultural sector. So, while expanding the scope and functions of this Bill, we have to consider how to give more assistance to the agricultural sector and for rural infrastructure. Unfortunately, I think, now the changes, somehow, don't link with the important work which this Bank has to do. Especially, in agriculture, the public sector investment has been coming down for the last so many years. There was huge investment, especially in the 80's. That is a fact. Because of this constant decline in the investment in agriculture, now, we are having a very difficult situation. The reports reveal the fact that the real growth in agriculture, in GDP terms, was just 1.9% in the last two-three years. But this year, it may be zero per cent, or, it may even go in the negative. You have to take note of that while considering a change for the rural infrastructure. Again, if we go through some of the important aspects of investment, which we need, what is the situation particularly with regard to the irrigation potential? If we see the enhancement of irrigation potential in our country, we find that from 1974 to 1980, the irrigation potential was increased to 1 million crore hectares. If we see the recent development in this area, we find that it has come down to just 0.4 million hectares. What does it mean? It means, investment in agricultural infrastructure is going down. We are facing problems, whether it is a question of irrigation facilities or giving financial assistance to the poor farmers or giving remunerative prices to the farmers. When you are making changes in the NABARD, you have to take note of all these changes which have taken place in the past. What is the credit situation for the poor people in the rural areas, and small farmers? If you see the credit movement ratio for rural areas, it was 33 per cent in the seventies. In the seventies and eighties, it increased steadily. There was an increase in the seventies and eighties. Now what is the situation? That trend has since reversed and in the nineties, we have reached where we were in the early seventies. That is the position now. The small farmers and the marginal farmers are facing an acute problem. What is the situation with regard to Backward Classes and SCs and STs? Earlier, the thrust was to give priority to these people. In the seventies, 60 per cent of assistance used

to go to these people. This was the concept. Further it was reduced to 40 per cent. Now what is the situation with regard to SC/ST and Backward Classes? These people do not have access to the financial assistance, which is available from the commercial banks or from the rural cooperative banks. Naturally, they are forced to take loans from the moneylenders. Now this is the present situation. When you are making these changes, you should be more careful in giving more assistance to the Backward Classes and SC/STs who are living in the rural areas. But, unfortunately, when you are making changes through this Bill, this aspect has not been covered properly. Instead of that, you are opening up your activities in other areas. You should give more assistance to the poor farmers. But, instead of doing that, what have you decided? You have decided to expand the scope of activities other than agriculture. The help is going to the NGOs. I think it is in tune with your new economic policy which is being pursued by your Government. There is a pro-rich attitude. Now big multinationals and big business people are entering agriculture because they do not need to give any extra tax on agricultural income. You are in tune with that policy. You are changing the attitude of the NABARD. The intention is to give more assistance to these people instead of giving it to the poor farmers and for developing the agricultural infrastructure. These resources are being channelised to rich people, big businesses and multinationals who are going to enter the agriculture of our country. That lacuna is very much there in this Bill and that should be taken note of. Again, regarding autonomy, you were explaining the changes for giving more autonomy to NABARD. But when while we go through the provisions regarding the Board of Directors, we find that instead of giving more autonomy, it gives more area to the bureaucracy inside this institution. We have a bitter experience. I am from a State where we have a democratic cooperative system. If you go through the records of NABARD regarding repayment, Kerala is the best. There is hundred per cent repayment by the cooperative sector. Naturally, to give some incentive to the peasants, we make a request to NABARD only to waive the interest rate for the peasants and not to waive the loan. What was their attitude? A highly bureaucratic attitude was shown to a State which is giving hundred per cent repayment by the cooperative sector. The decision was, NABARD is against waiving the interest on the loan. Again I met the NABARD people. They said, because of the instructions of the Reserve Bank, we are not going to assist the peasants. What kind of peasants? They are taking loan; they are repaying it in time. They are giving the interest. Give some assistance to

them, some incentive to them. The bureaucratic attitude was very much there in the Reserve Bank of India. Through the proposed Bill, you are putting more bureaucratic control around the neck of the NABARD. I would like to know how you are going to help. Here, a proper representation is not there for the farmers, for the agricultural workers and the for the cooperative sector. How are you going to fill that area in this Bill? That should be explained properly. These are the two areas. At the outset, whatever money we are collecting for NABARD should be given for agriculture and development of the agricultural and rural infrastructure, and bureaucratic control should be reduced. Proper representation should be given to agricultural workers, peasants and those who are working in the agricultural sector. These are the two issues which I wanted to raise before this august House and, through you, before the Minister.

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभापति महोदया, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2000 जो आया है, इसके आने के बाद ऐसा लगता है कि सरकार की सोच गांवों के प्रति बढ़ती जा रही है। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि जो पूंजी गांवों के विकास के लिए "नाबार्ड" के पास थी, उसको बढ़ाया जा सकता है, यह एक अच्छी बात है। लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि "नाबार्ड" की स्थापना जिस उद्देश्य के लिए की गई थी, जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी, उस बारे में अब तक उसका कार्यकाल कैसा रहा, क्या इसकी समीक्षा की गई है? नाबार्ड जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, उस उद्देश्य को उसने पूरा किया है या नहीं?

महोदया, आज गांवों की स्थिति बहुत दयनीय है। अभी सुरेश पचौरी जी कह रहे थे कि देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में खेती पर आधारित है, इसलिए यदि हम खेती के संसाधन पूरी तरह से नहीं जुटा पाएंगे तो जिस प्रकार का आज दुनिया में कम्पिटिशन चल रहा है, हम पीछे रह जाएंगे। आज स्थिति ऐसी है कि हमारे देश का किसान जो खेती की पैदावार करता है, उसका उचित मूल्य भी उसको नहीं मिल पाता है। हमारे पास ऐसी भी व्यवस्था नहीं है कि आज की नई टेक्नोलॉजी के लिए उसको पैसा मिल सके और इस नई टेक्नोलॉजी से वह अच्छी पैदावार कर सके। आज जब हम अपने देश के किसान की हालत को देखते हैं और दूसरे देशों के किसान से उसकी तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा किसान बहुत पीछे है और बड़ी दयनीय अवस्था में है। महोदया, आज अगर हम गांवों में सड़कों की स्थिति को देखें या स्कूल के भवनों की स्थिति को देखें तो उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। आज 50 सालों की आज़ादी के बाद भी हम अपने किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। नाबार्ड से हमें पैसा मिलता रहा लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हुआ। जो पैसा मिला है वह केवल कागजों के ऊपर है या किसी विभाग को दे दिया गया है। यह पैसा सड़कों के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के पानी की योजनाओं के लिए दिया गया है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हुआ है और वह पैसा काम में नहीं आया है। इस पैसे के माध्यम से किसान को जितनी सुविधा मिलनी चाहिए थी, उतनी सुविधा किसान को अब तक नहीं मिली है।

3.00 P.M.

महोदया, इस बिल में मंत्री जी ने यह जरूर किया है कि बोर्ड के अंदर डॉयरेक्टर्स की संख्या बढ़ाई है और स्वतंत्र रूप से काम करने की प्रणाली को स्थापित किया है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर्स में ग्रामीण एरिया के लोग हों, गांवों में रहने वाले लोग हों, शैड्यूल्ड कास्ट्स ऐंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हों क्योंकि वे ही वास्तव में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। महोदया, वास्तविकता तो गांव के लोग ही समझते हैं। अधिकारियों को तो पता ही नहीं है कि गांवों में आदमी कैसे रहते हैं, उनके क्या दुःख हैं, उनकी क्या तकलीफें हैं और कैसे उनको दूर किया जा सकता है, किस प्रकार से लोन लेने में उनको कठिनाइयां होती हैं। इस कष्ट को तो गांव का आदमी ही समझ सकता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर्स में आप पिछड़ा के लिए, एस.सी./एस.टी. के लोगों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करें।

महोदया, आज सिंचाई और पीने के पानी की योजनाओं की स्थिति यह है कि किसान के सिंचाई के जो साधन थे, वे आज समाप्त होते जा रहे हैं। आज अंडरग्राउंड पानी का लेवल बहुत नीचे गिर गया है। इस जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा तालाब बनाने के लिए पैसा लगाना चाहिए। खेती को अगर पानी नहीं मिलेगा तो किसान खेती नहीं कर सकता है। आज पानी न मिलने के कारण खेती की दयनीय स्थिति है और किसान की स्थिति भी दयनीय है। महोदया, मैं जिस स्टेट से आता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान में नाबार्ड का पैसा लगाने की ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि 50 सालों की आजादी में 40 साल हमारे यहां सूखा रहा है। हमारे यहां किसी न किसी एरिया के अंदर हर साल सूखा पड़ता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे यहां सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए अधिक से अधिक तालाब बनाए जाएं जिससे पानी का स्तर ऊपर आ सके और किसान को सुविधा मिल सके।

महोदया, आज राजस्थान में सड़को की स्थिति भी बहुत दयनीय है। इसके लिए आप पैसा तो बढ़ा रहे हैं लेकिन कहां ऐसा न हो जाए कि यह पैसा दूसरे कामों में लगा दिया जाए। गांव के विकास के लिए जो पैसा बढ़ाया जा रहा है, यह दूसरी मदों में खर्च नहीं होना चाहिए जैसा कि अब तक होता आया है। इसी प्रकार से जो कर्ज किसानों को दिया जाता है, उसमें भी उनको कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप कर्ज देने की प्रक्रिया को लचीला बनाइए और नाबार्ड के माध्यम से बैंकों को निर्देश दीजिए कि वे कर्ज देने की प्रक्रिया को सरल और लचीला बनाएं ताकि गांवों के लोगों को कर्ज लेने में कोई परेशानी न हो। कई बार बैंकों के अधिकारी भी अड़चनें पैदा कर देते हैं। कई प्रकार की कार्यवाहियां बैंकों में होती हैं, वहां कई प्रकार का करप्शन होता है। आज यह स्थिति देखने को मिलती है कि किसानों को जितना लोन मिलता है उसका कुछ परसेंटेज बैंक वाले रास्ते में अपने कमीशन के रूप में ले लेते हैं। इस तरह किसान को उस कर्ज का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए इसकी समीक्षा के लिए आपको कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। आप यह समीक्षा करें कि बैंकों के जो अधिकारी हैं, वे किसी प्रकार के घोटाले में लिप्त नहीं हैं, किसान को कर्ज वास्तविक रूप में दे दिया गया है और उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं। महोदया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस देश के अंदर कृषि को बढ़ावा दें तो निश्चित तौर से गांवों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और वे खुशहाल हो सकते हैं। आज ज्यादातर अपराध और कुछ ऐसे लोग इसलिए बंद रहे हैं क्योंकि लोन लेने के अंदर और लोन चुकाने के अंदर दो तरह की नीति इस देश के अंदर चल रही है। आज हम इण्डस्ट्रीज को लें, उद्योगों को लें। उद्योगों के लिए लोन लेने वालों के

ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है जबकि एक छोटे किसान ने अगर पम्प सैट के लिए लोन लिया, नाबार्ड के बैंको से पैसा लिया तो लोन की शर्तों के अनुसार उसकी जमीन गिरवी रख ली जाती है और जब बड़े बड़े उद्योगों को लोन दिया जाता है तो उनके ऊपर ऐसी किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं होती है तथा उन्हें बड़े बड़े लॉन दे दिए जाते हैं। पहली बात तो यह है कि वे लोग लोन लेने के बाद इण्डस्ट्री लगाते नहीं हैं और अगर इण्डस्ट्री लग भी जाती है तो उसमें से कुछ पैसा बचा लिया जाता है तथा इण्डस्ट्री को फेल कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इसमें से पूंजी निकालने के लिए उस पर ऐसी कोई रोक नहीं है। बल्कि उस इण्डस्ट्री को चलाने के लिए पुनः लोन दे दिया जाता है। जबकि गांव में रहने वाला किसान यदि पम्प सैट या ट्रैक्टर के लिए या अपनी खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए, सिंचाई के लिए, पानी की व्यवस्था करने के लिए लोन लेता है तो पहले उस ग्रामीण से उसकी जमीन को गिरवी रखने का एक पट्टा ले लिया जाता है। उसके बाद अगर वह लोन नहीं चुकाता है तो उसकी जमीन को बैंक अपने अंदर ले लेता है, बैंक उससे छीन लेता है। इस प्रकार उसकी ऐसी दुर्गति होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रकार किसान और इण्डस्ट्री के बीच में जो भेदभाव है उसको कम करें, जो किसान के साथ बदसलूकी की जाती है वह न की जाए तथा अगर किसान एक बार लोन लेता है और उस लोन को वह चुका नहीं पाता है तो उसको चुकाने के लिए अगर उसको और लोन की आवश्यकता है तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि उसको और लोन दिया जाए जिससे वह अपने संसाधन बढ़ाकर पुराने लिए हुए लोन को भी चुका सके। ऐसी व्यवस्था आप करें तो इससे निश्चित रूप से किसान को राहत मिलेगी।

मैं यह मानता हूँ कि इस बिल के बनने के बाद किसान को कुछ तो राहत मिलेगी। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री सोलीपेटा रामचन्द्रा रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं इस नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एंड रूरल डवलपमेंट ऐक्ट, 1981 को सम्पूर्ण समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूँ मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से। इसमें यो तो कई अंश हैं, लेकिन कुछ अंशों पर मैं अपना विचार पगत करना चाहता हूँ। 1981 में जो ऐक्ट बनाया गया और 1982 में जो यह नाबार्ड स्थापित किया गया यह केवल कृषि विकास के साथ साथ स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज, कॉंटेज इण्डस्ट्रीज, रूरल डवलपमेंट के लिए, ग्रामीण विकास की मदद करने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन आज 18 साल हो गए हैं। अगर हम पीछे देखें कि हमारा 18 साल का क्या अनुभव है, तो जितनी प्रगति होनी चाहिए, जो विकास होना चाहिए उस विकास में बहुत कमी हुई है। मंत्री जी के शब्दों में कहना पड़ेगा कि इसकी वजह कुछ बोटलनेक्स, कुछ शोर्टकमिंग्स वगैरह रही हैं। यह केवल रिफाइनंसिंग एजेंसी है। स्टेट कॉर्पोरेशन बैंक को, रूरल बैंक को और कुछ कॉमर्शियल बैंक को भी केवल कृषि विकास के लिए यह उनको फाइनेंस करते हैं और इसका प्रधान उद्देश्य उस दिन जो दोनों सदनों में सोचा गया और जो बनाया गया वह केवल एग्रीकल्चर वगैरह के लिए जो लोन चाहिए उसके ताल्लुक से सोचा गया वह आज तक भी पूरा नहीं हुआ। कृषि की जो डिमांड है, जो नेसेसिटी है, जो अवसर है उसका आधा भी यह कोऑपरेटिव बैंक, रूरल बैंक और कॉमर्शियल बैंक सब मिलाकर के पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज भी रूरल एरिया में गरीब किसान बड़े बड़े साहूकारों के पास जाकर 20, 25 और 30 परसेंट के इंटरेस्ट पर लोन लेने के लिए मजबूर हैं। यह जो पांच हजार करोड़ रुपये का वर्किंग कैपिटल देश का बढ़ाया है इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूँ, इसको पहले सेन्ट्रल गवर्नमेंट चलाती थी

उसकी जगह पर अब इस अमेडमेंट बिल के जरिए से जो बोर्ड को अधिकार दिए गए हैं, में उसका भी स्वागत करता हूँ। अब ज्यादा आटोनोमी दी गई है लेकिन कभी-कभी आटोनोमी कागजों में ही रह जाती है इसलिए मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बात का ख्याल रखें कि यह आटोनोमी पेपर्स में ही न रह जाए बल्कि वास्तविक रूप ले। मेरे से पहले भी कुछ ऑनरेबल मेम्बर्स ने डायरेक्टर्स के बारे में फरमाया है जो कि 6(बी) में है। इसमें कुछ मोल कहा गया है। इस डेमोक्रेटिक दौर में आजादी हासिल करने के 50 साल बाद भी अगर हमारी सोच ऐसी है तो फिर हमें मजबूरी का इजहार करना पड़ता है। इससे पहले जो बिल है उसमें डायरेक्टर्स के बारे में क्लियर है, Out of the three Directors, two Directors shall be with an experience of working in the cooperative banks and one shall be with an experience of working in commercial bank. तो इसमें (बी) और (सी) को पांच में एक जगह मिलाकर नये अमेडमेंट में तीन करके कोआपरेटर्स हैं उनको बिल्कुल निकाल दिया गया है। मैं आपसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे हिन्दुस्तान के कोआपरेटिव मूवमेंट के श्री बालासाहेब विखे पाटिल एक मशहूर हस्ती हैं। बाबासाहेब विखे पाटिल इस मिनिस्ट्री में मंत्री हैं और उन्होंने इस बिल को पेश करते वक्त कोआपरेटिव बैंकों के प्रेसीडेंट्स को निकाल कर बाहर कर देने का जो प्रावधान किया है इसका मुझे बहुत अफसोस है, तकलीफ है और मैं अपना दुख प्रकट करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोआपरेटिव मूवमेंट की इज्जत बचाने के लिए कम से कम बाबासाहेब विखे पाटिल मेरी इस मांग को अब भी मान लेंगे। आपने अमेडमेंट के जरिए से इसमें कई अच्छी बातें कही हैं। आपका पूरा पैसा ज्यादातर कोआपरेटिव सैक्टर में जाता है और रीजनल रूरल बैंक में जाता है। वह ही एक कोआपरेटिव सैक्टर है जिसमें नान-आफिसियल रिप्रजेंटेटिव रहते हैं जबकि रीजनल रूरल बैंक आफीसर्स से चलाया जाता है, कामर्सियल बैंक आफीसर्स से चलाया जाता है। जहां पर रियल रिप्रजेंटेटिव ऑफ द फारमर्स रहते हैं, आपने उसके डायरेक्टर्स को निकालकर बाहर फेंक दिया है। यह बिल्कुल बुरी बात है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं अब भी रिक्वेस्ट करता हूँ और मुझे विश्वास है क्योंकि मंत्री जी का कोआपरेटिव मूवमेंट से संबंध रहा है, वे इसको फिर से ऐड करेंगे और इसको नहीं निकालेंगे। इसमें एक बात कही गई है जिसको गौतम जी ने भी फरमाया है, "Provided that until the assumption of charge by the elected Directors under this clause..." क्या मतलब है, मतलब इलेक्शन हो गया है, लेकिन वह चार्ज अजेम्पशन नहीं दिया है ऐसा मतलब इसमें निकल रहा है। इलेक्शन होने के बाद आप चार्ज क्यों नहीं लेने देते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए। वह इक्युटी नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, इलेक्शन नहीं हुआ है तो चार्ज रिज्युम करने का सवाल ही नहीं होता है और आपको द्वारा भी नोमिनेट करने का सवाल पैदा नहीं होता है। इसके बारे में भी मैं क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ। अगर इक्युटी के लिहाज से डायरेक्टर्स चुने गए तो फारेन रिजमेशन स्टार्ट होना चाहिए। अगर इलेक्ट नहीं हुए तो छोड़ दीजिए, बाकी जो रिमैनिंग डायरेक्टर्स हैं उनसे आप काम चलाइये। यह मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरी बात मैं चेयरमैन के संबंध में अर्ज करना चाहता हूँ। चेयरमैन के तात्लुक इसमें कहा गया है कि अगर चेयरमैन की किसी न किसी वजह से पोस्ट खाली है तो मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन बन जाएगा ऐसी बात कही गई है। इसके पहले के सेशन में वैसा नहीं है। इसके पहले के सेशन में कहा गया है, "The Chairman of the Board, if for any reason, is unable to attend any meeting, any other Director nominated by the Chairman in his behalf, and in the absence of such nomination,

any other Director elected by the Directors present at the meeting shall preside over the meeting of the Board." यह बहुत डेमोक्रेटिक है आप उसको निकाल देंगे। अगर चेयरमैन की किसी न किसी वजह से पोस्ट खाली है तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर को चेयरमैन बना देना चाहते हैं, यह तो गोइंग बैक है, यह डेमोक्रेसी की बात नहीं है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वह खुद चेयरमैन बनना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चेयरमैन की पोस्ट खाली क्यों रहती है? आपने उसको पांच साल के लिए नोमिनेट किया है, आप पांच साल पूरा होने से पहले ही दूसरे चेयरमैन को नोमिनेट कर दीजिए। अगर किसी वजह से वह चेयरमैन नहीं आ सका, राजीनामा लेकर चला गया या कुछ और हो गया तो कम से कम Within 15 days another Chairman should be nominated without expressing any reasons. This is my request to the hon. Minister. लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन बनेगा, यह बहुत बुरी बात है, ऐटी डेमोक्रेटिक बात है, यह मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूँ। महोदया, मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूँ कि ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को रीफाइनस करते हैं। यह बहुत अफसोस की बात है कि आज जब हम हर लम्हे ग्रामीण विकास और कृषि विकास की बात करते हैं, उसके बावजूद 1 अक्टूबर 99 को अब्जानक उनके इंटरस्ट में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी। इसकी कोई वजह आज तक ये नहीं बता सके हैं और न ही मैं समझ सका हूँ। मैंने इस संबंध में रिजर्व बैंक से भी बात की। आपने जो 1.5 परसेंट पर-एनम जो इंटरस्ट बढ़ाया है, यह कृषकों के खिलाफ है। इसलिए मैं मंत्री जी से रिक्वैस्ट करता हूँ कि 1 अक्टूबर 99 से जो आपने इंटरस्ट बढ़ाया है, उसको वापिस ले लें। इसके साथ साथ कृषकों को ऋण देने में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, जैसा कि मीणा जी ने भी बताया है। नीचे के लेवल पर जो कठिनाइयाँ हैं, उनको दूर करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक आफिसर रहता है - नाबार्ड के लोग वहाँ कभी-कभी सरप्राइज विजिट करके उनकी इन कठिनाइयों को देखकर उन्हें दूर करने के लिए नैसेसरी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। इसके अतिरिक्त महोदया, जब रिकवरी की बात आती है तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कभी कोई नैचुरल कैलामिटी आ जाए, जैसे फ्लड आ गया या सूखा पड़ गया तो उनकी पूरी फसल तबाह हो जाती है और ऐसी स्थिति में भी उनसे ऋण वसूल किया जाता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसी स्थिति में किसानों को आपके पास आकर स्थिति का बयान करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बैंक वालों को आपको अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, वहाँ क्या हो रहा है, उसकी सारी रिपोर्ट्स आपके पास आती है। आपको अपनी तरफ से उन हालात में उनके ऋण की रिकवरी को कम से कम एक साल के लिए रोक देना चाहिए ताकि उनको कुछ शहत मिल सके। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

प्रो. रामदेव भंडारी (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदया, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना ही इस उद्देश्य से की गयी थी कि गांव में रहने वाले 70 प्रतिशत जो किसान और कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी समृद्धि और विकास के लिए इस बैंक के माध्यम से जो भी संभव हो, वह किया जाए। महोदया, यह फाइनेंसिंग बैंक है जिसके द्वारा किसानों को री फाइनेंसिंग होती है। महोदया, इस वर्तमान सत्र में दोनों सदनों में किसानों के बारे में सवाल उठाए गये हैं। आज भारत का किसान आत्महत्या कर रहा है, अपनी फसल को जला रहा है और धुँक वह अपना कर्ज वापिस नहीं कर सकता है इसलिए या तो अपनी जमीन बेच रहा है या गांव छोड़कर शहर की ओर भाग रहा है ताकि शहर में जाकर थोड़ी बहुत कमाई कर सके जिससे परिवार का गुजारा कर सके। इस बैंक का उद्देश्य और इसका लक्ष्य बहुत अच्छा है और थोड़ा

बहुत इन्होंने इस क्षेत्र में काम भी किया है मगर महोदया, किसानों को इससे जो लाभ होना चाहिए था, जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि लोन मिलने में किसानों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नाबार्ड जिस बैंक से किसानों को लोन देता है, उस बैंक के स्तर पर भी कठिनाइयाँ होती हैं और लोन लेने में भी - चाहे ऑफिशियल लेवल पर हो, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर हो या दूसरे स्तरों पर हो - उन्हें कठिनाई होती है। उसमें बिचौलिये आते हैं और उन्हें पूरा लोन नहीं मिल पाता है। फिर जब लोन वापिस करने की बात होती है तो कर्ज के साथ-साथ सूद भी उनको देना पड़ता है। महोदया, हमारे रेड्डी साहब ठीक कह रहे थे कि भारतीय किसानों की जो फसल होती है, वह सुनिश्चित नहीं होती है। कभी अकाल, कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ - कई तरह की समस्याएँ उन किसानों के सामने होती हैं। जिसकी वजह से उनकी फसल मारी जाती है और वे कर्ज लौटाने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसी अवस्था में, ऐसी विपत्ति में नाबार्ड का जो कर्ज होता है, उस कर्ज पर जो सूद होता है, उसे माफ करने के संबंध में इस बैंक को विचार करना चाहिए क्योंकि अगर किसानों को कर्ज के साथ-साथ सूद भी देना पड़ेगा और फसल भी नहीं होगी तो किसान इसे बरदाश्त नहीं कर सकेंगे।

महोदया, अभी एक माननीय सदस्य डायरेक्टर्स की बात कर रहे थे। हम कहते हैं कि लोग फाईव-स्टार होटल में बैठकर किसानों की समस्या की चर्चा करते हैं। जिन्हें कृषि से कोई मतलब नहीं, जो सिर्फ किताबों में ही जानते हैं कि कृषि क्या होती है, खेती क्या होती है, वे फाईव-स्टार होटलों में बैठकर किसानों की समस्या की चर्चा करते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखेंगे तो क्या होगा? वे तो सचमुच में किसान भी नहीं होते हैं और वे किसानों की समस्याओं को सही तरीके से आँक भी नहीं सकते हैं।

महोदया, आजकल फार्म हाऊस का नाम सुनाई देता है। फार्म शब्द उससे जुड़ा हुआ है लेकिन नाम तो उसका फार्म हाऊस है तो उसकी मनोरंजन गृह कहे या रिक्रिएशन गृह कहे, इस तरह के फार्म हाऊस में बैठकर हम अगर...

उपसभापति : किसान हाऊस कहना चाहिए या किसान गृह उसे कहना चाहिए।

प्रो. रामदेव भंडारी : हाँ महोदया, हम उसको कोई भी नाम दे दें फार्म हाऊस के बदले में तो उसका जो काम है, वह काम किसानों से जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए फाईव-स्टार होटलों में बैठकर किसानों की समस्या पर चर्चा न हो और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसान के रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेंगे, अगर कौऑपरेटिव सेक्टर के जो लोग हैं जिनका काम किसानों से जुड़ा हुआ है, वे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं रहेंगे या दिल्ली और मुंबई में बैठने वाले लोगों को हम डायरेक्टर्स बनाएँगे तब तो समझिए किसानों की समस्या सुलझने से रह गई। इसलिए महोदया, सचमुच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसानों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए।

महोदया, एक बात और कहना चाहूँगा कि किसानों की समस्या को जानने के लिए जिला स्तर पर तो संभव नहीं होगा इसलिए राज्य स्तर पर किसानों का सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए और उनको कृषि में क्या कठिनाई है, उनकी बात सुनी जाए और उनकी बात सुनकर उस पर विचार किया जाना चाहिए। इस तरह से किसानों की समस्या के बारे में नाबार्ड को जानकारी मिलेगी। बड़े किसान जो हैं, वे इससे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। जैसे अभी ट्रैक्टर की बात है, अभी जो गाँवों में लोन मिलता है, अगर ट्रैक्टर के लिए आप लोन लेना चाहें तो आसानी से आपको

लोन मिल जाएगा। बैंक भी ट्रैक्टर को-फाइनेंस करने के लिए आसानी से तैयार हो जाता है मगर पशु हैं, गायें हैं, भैंसें हैं या कम एमाउंट का लोन जो होता है, उस लोन को देने में बैंक भी बहुत हिचकिचाता है। कहता है कि हमारा यह लोन वापस नहीं होता है। महोदया, लोन वापस होता है और जो सचमुच के किसान हैं, वे अगर लोन लेते हैं तो उनको यह भय होता है कि अगर हम लोन वापस नहीं करेंगे तो हमारी कुर्की-ज़बर्ती हो जाएगी और वे हमारे बैल और दूसरे जो पशु हैं, उनको उठा कर ले जाएंगे। मगर नकली लोगों को जो लोन दिया जाता है, दैसे लोग लोन वापस नहीं करते हैं और बदनाम किसान हो जाते हैं। इसलिए एक मॉनीटरिंग की भी आवश्यकता है। अब नाबार्ड तो प्रखंड स्तर तक या जिला स्तर तक मॉनीटरिंग नहीं कर सकता है मगर राज्य स्तर तक मॉनीटरिंग की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। वह पदाधिकारी जिले में जाए, एक टीम या कोई थ्रु हो पदाधिकारियों का, वह जिला स्तर पर जाए और मॉनीटरिंग करे कि सचमुच में नाबार्ड का जो पैसा है, वह किसानों को जा रहा है या नहीं। किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं, इस मॉनीटरिंग की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। महोदया, यह जो बिल किसानों की प्रगति और विकास के लिए लाया गया है, मैंने कुछ बातें अपनी ओर से रखी हैं। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूँ, धन्यवाद।

SHRI KA. RA. SUBBIAN (Tamil Nadu): Thank you, Madam, for having given me this opportunity to express my views on the National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Bill, 2000. Though the original Act was enacted in the year 1981, the (Amendment) Bill has been brought now by the hon. Finance Minister. The amendment sought in this Bill is that the capital has been increased from Rs. 500 crores to Rs. 5,000 crores. I welcome the Bill for the following reasons. We could see in the Bill that in respect of 26 sections, amendments have been brought by way of additions, deletions, insertions and substitutions. Not only has the capital been increased from Rs. 500 crores to Rs. 5000 crores, further, the Board of Management has been constituted in accordance with the provisions contemplated in the Bill. That apart, the reason for my welcoming the Bill is that, now among the Board of Directors, four directors from the State Government officials could participate. Such a provision has been contemplated in the Bill. As far as the D.M.K. party is concerned and the State is concerned, we are pleading for the State's autonomy, and now, in this Bill, a provision has been made allowing the participation of four directors. In the Objects and Reasons of the Bill, we could see the reason for bringing forward this Bill. While implementing the provisions of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981, several bottlenecks and shortcomings have come to light. Hence, with a view to removing them and providing functional autonomy and operational flexibility to the banks as well as expanding its role and augmenting its resources to make it a strong, self-reliant and more vibrant institution so as to effectively save the agriculture and rural sector in

consonance with the present policy of liberalisation and reforms, several amendments have been brought in this legislation. As far as NABARD is concerned, people get the financial help through the National Bank for Agriculture and Rural Development, which is an Apex Development Bank in the field of agriculture and rural development. Its main function is to provide refinance to various functioning institutions, such as State Cooperative Banks, Regional Rural Banks and Commercial Banks for promotion of agriculture, small-scale industries, cottage and village industries and allied activities in rural areas with a view to promoting integrated rural development and securing prosperity for rural areas. So, the sole and the main objective of NABARD is to finance the banks which have been mentioned by me, and through those banks, the people are deriving the help. In the Preamble, it is stated:

"An Act to establish a development bank to be known as the National Bank for Agriculture and Rural Development for providing and regulating credit and other facilities for the promotion and development of agriculture, small-scale industries, cottage and village industries, handicrafts and other rural crafts and other allied economic activities in rural areas with a view to promoting integrated rural development and securing prosperity of rural areas and for matters connected therewith or incidental thereto."

Madam Deputy Chairperson, as far as India is concerned, it is agriculture oriented country, and if we take into consideration the agriculturists and also the people who are involved in village industries, handicrafts and other rural crafts and other allied economic activities in rural areas, definitely, out of 100 crores of people, more than 80 crores are involved in all these professions, namely, agriculture and other professions. My respectful appeal to the Minister is this. As far as India is concerned, by straining every nerve, the village agriculturists and their womenfolk have brought the production of foodgrains, namely, wheat, paddy and other grains, and have converted India into a surplus State. My hon. friend and a senior Member, Mr. Gautam, when he addressed the issue, brought to the attention of the hon. Minister that amongst the Directors, who are going to take part in the Board of Management, the agriculturists are not included. In the proviso it is stated:

"Provided that until the assumption of charge by the elected directors under this clause, the Central Government may at any time nominate such number of

[20 December, 2000] RAJYA SABHA

directors not exceeding four from amongst persons having special knowledge of, and professional experience in, agricultural science, technology, economics, banking, co-operatives, law, rural finance, investment, accountancy, marketing or any other matter, the special knowledge of, and professional experience in, which would, in the opinion of the Central Government, be useful to the National Bank for carrying out its functions."

I appeal to the Minister that there should be a mandatory provision. The Central Government shall nominate not less than four directors, and that too, after removing all these provisions, there should be tillers of the soil only. From amongst the agriculturists, four directors should be nominated on the Board of Management. Not only that; as far as India is concerned, all the womenfolk are working like anything. In fact, they work more than men in villages to augment the production of foodgrains. On a perusal of this Amendment Bill, I was not able to see any provision in this Bill for the nomination of women-directors. We see that everywhere a voice is being raised that 33 per cent seats should be reserved in the Assemblies and in the Parliament. When the womenfolk are involved in agricultural operations, there should also be a provision in this Bill for participation by women-directors. Therefore, I appeal to the hon. Minister that suitable provisions should be made in this Act to ensure the participation of women directors so that they can raise their voice, as and when the necessity arises.

Apart from that, there is one more appeal, Madam. As far as the authorised capital is concerned, this amount of Rs.5,000 crores is very meagre. If you take the population of this country into consideration--now, it is 100 crores--if you take this 100 crores of people as a bank, every year, one-and-a-half crores of people are deposited in this population bank. Likewise, the authorised capital of this Bank should also be increased so that all these refinancing institutions, the State Co-operative Societies and other banks, would be able to help the agriculturists and also the people engaged in small industries, handicrafts, and others which are mentioned here in this Bill. I appeal to the hon. Minister that these things should also be taken into consideration. With these words, I thank you, Madam, for giving me this opportunity. I support and welcome this Bill, on behalf of our party which is a partner in the NDA Government.

उपसभापति : बैंक यू. मंत्री जी। दो चीजें आपके ध्यान के लिए हैं। एक तो आपने कोआपरेटिव के लोगों को उसमें शामिल नहीं किया और दूसरे महिलाओं का प्रोटेक्शन नहीं किया। यह जरूरी है, क्योंकि गांवों में वैसे भी इंडस्ट्रियल बैंक के यू जो महिला एंटरप्राइज कोई लोन लेने जाती हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है। उनसे एशोरेस मांगते हैं, प्रोटेक्शन मांगते हैं, जबकि उनके पास नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब यह ग्रामीण विभाग में कोई महिला चली जाएगी तो उसको कितनी तकलीफ होगी। इसलिए जब आप जवाब देंगे तो कृपया इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास इसका क्या जवाब है। क्या रीजन है कि आपने महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के बारे में इसमें ध्यान नहीं दिया है? ... (व्यवधान)...

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) : मैडम, लड़कियों को तो देते ही नहीं हैं। ... (व्यवधान)...

उपसभापति : वही बात हो रही है। ... (व्यवधान) ... डायरेक्टर की बात हो रही है, क्योंकि यह कोई डायरेक्टर होगी तो इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकेगी कि गांवों की महिलाओं की क्या प्रॉब्लम है। वैसे अभी जवाब देने का टाइम नहीं आया है, यह तो मैंने खाली ऍड ही किया है। बोलने वाले अभी दो-तीन लोग और बचे हैं। अभी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जवाब देते वक्त ये सब बातें भूल जाते हैं। ... (व्यवधान) ... तीन लोग और हैं, उसके बाद जवाब होगा।

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदया, आपने इस बिल पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात कहने से पहले एक बात विशेष तौर से, जैसा कि पहले भी एक सदस्य महोदय ने इशारा किया है, कर देना ठीक समझता हूँ कि इस बिल को जिन महानुभाव बालासाहेब दिखे पाटील ने सदन के सामने रखा है, मैं निजी तौर से जानता हूँ कि वे एक किसान हैं और बहुत अच्छे किसान हैं, वे जिस बिस्तर पर अपने घर में आराम करते हैं, वे किसी फोम के गद्दे पर नहीं, बल्कि धान की बोरियों पर ही सोते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। चूंकि इनसे मैं थोड़ा वाकिफ हूँ, ऐसा व्यक्ति जब इस बिल को यहां पर पायलट करे तब उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक इसमें भारतीय किसान का लाभ निहित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन जिस भी सदस्य ने, जिन भी विद्वान सदस्यों, महानुभावों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं उन्होंने अपनी धिताएं जरूर व्यक्त की हैं और उन धिताओं का आलेखन मंत्री महोदय कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं और उत्तर भी हम उनसे चाहेंगे। अब कुछ बातें स्पष्ट कर लें। आपने डायरेक्टर्स के बारे में जो इसमें नया प्रोविजन किया है, एक बात तो यहां से आ गई और चेंबर से भी आ गई कि कम से कम आप 19 डायरेक्टर्स जो बना रहे हैं उनमें तीन-चार बहनें जरूर शामिल हों, करना आपका यह बोर्ड अधूरा रहेगा। आप चाहे 19 पुरुष कर लें तो भी देश के साथ न्याय नहीं हो पाएगा जिस देश में 49 फीसदी आबादी महिलाओं की हो उनका एक भी सदस्य हम इसमें नहीं रखें तो यह कोई न्याय नहीं होगा। एक तो कृपा करके आप इस सुझाव पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। दूसरा निवेदन यह है कि जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन करें तो भारत कृषक समाज का भी कम-से-कम एक डायरेक्टर जरूर रखें। यह किसानों की एक बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है और इस में आप ने खुद भी एक बड़ी भूमिका अदा की है। देश के करीब साठे 5 लाख गांवों में इस संस्था के सदस्य पाए जाते हैं। उस का डायरेक्टर रखने से आप का काम भी हल्का होगा।

मंत्री जी, एक चीज की तरफ शायद जल्दबाजी में या हड़बड़ी में आप का ध्यान न हो गया होगा और इस के लिए ऑर्डिनेंस लाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप घबराकर किसी-न-किसी कारण से ऑर्डिनेंस ले आए। इस में एक चीज आप के दिमाग से निकल गयी या आप के ऑफिसर्स ने उस ओर संकेत नहीं किया। इस में जगह-जगह आप ने भूमि विकास बैंक का जिक्र किया है। उपसभापति महोदया, भूमि विकास बैंक प्रदेशों के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन आप को जानकारी होगी कि एक-दो प्रदेशों में भूमि विकास बैंकों का नाम बदल दिया गया है हालांकि काम नहीं बदला है। महोदया, मध्य प्रदेश विधान सभा की अनुज्ञा से इस बैंक का नाम बदल दिया गया है। मुझे भी उस का ठीक-ठीक नाम याद नहीं है, इसलिए मैं अप्रामाणिक नाम नहीं देना चाहता हूँ। तो यह भी आप स्पष्ट कर दीजिए वरना भूमि विकास बैंक तो वहां है ही नहीं।

महोदया, भंडारी जी अभी बोल रहे थे। उन्होंने बहुत बुनियादी बातें कही। महोदया, जहां तक कृषकों के विकास की बात है या कृषि के विकास की बात है, उस विषय में इस देश में कोई विवाद नहीं है। इस मामले में आप से हम सब सहमत हैं, लेकिन इस देश में कृषक कौन है, इस पर कभी आप ने सोचा है? जिस के नाम पर खेती होती है, उस को आप किसान मान लेते हैं। मेरे खुद के नाम पर दो एकड़ जमीन है। आप मुझे किसान मान लेते हैं, लेकिन अपने खेत की मेढ़ पर गए हुए मुझे 15 वर्ष हो गए। मैं किसान हूँ और जो वहां किसानी का काम करता है, वह मजदूर कहलाता है। जो खेत पर जाता भी नहीं वह किसान कहलाता है। इस विसंगति की ओर भी आप को बैंकों को निर्देश देने चाहिए।

मैं आप से एक विशेष निवेदन और करना चाहता हूँ। बैंकों में किसान के साथ क्या व्यवहार होता है? एक व्यक्ति जो बैंक को सौ, दो सौ करोड़ रुपए की चपत लगा देता है और बैंक में जाता है तो बैंक मैनेजर उस का उठकर स्वागत करता है पर जब उसी बैंक में एक किसान कर्ज मांगने जाता है तो उस को टाल दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि बुधवार को आना या गुरुवार को आना। उस के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं होता है। वह जिस लोन को लेने के लिए जाता है, उस की राशि का आकलन पहले किया जाता है। मंत्री जी आप के पास मिशन है, लेकिन बैंकों में कमीशन है और इस मिशन और कमीशन के बीच में किसान पिसता चला जा रहा है। इस पर भी आप को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

मंत्री जी, एक निवेदन मैं और करूंगा। आप ने आर.बी.आई. के अधिकारियों से शायद पूछा होगा और अगर नहीं पूछा है तो अपने चैम्बर में उन से पूछिए कि फसूली ऋण का कितना रुपया उन्होंने रोक रखा है? महोदया, आर.बी.आई. ने फसूली ऋण का 5700 करोड़ रुपया रोक रखा है। यह कोई छोटी राशि नहीं है। मंत्री जी, आप याद रखिए कि जब यह रुक जाएगा तब किसान कहा जाएगा? वस्तुतः फिर वह आत्महत्या करेगा। कर्जा नहीं चुका पाएगा और उस के बाल-बच्चे परेशान होंगे।

मंत्री जी, अभी गीतम जी ने बहुत बुनियादी बातें अपने अनुभव के आधार पर कहीं। आप उन को रेखांकित कर लीजिए। आज आप हम किसानों के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं, लेकिन क्या कारण है कि इस देश में किसान का बेटा किसान बनने को तैयार नहीं है। वह हमारे पास नौकरी की तलाश में आता है। और हम सबके पास आकर वह दूसरी बात करता है और यदि मैं आपका चार्ट देखूँ तो आपका चार्ट ठीक है। आपने बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हैं, जून, 1983 से 31 मार्च, 2000 तक के आंकड़े आपके सामने फैले हुए हैं। जून, 1983 तक, यानी उन गए दो-तीन

साल में, आपके पास कुल सोर्सिस थे 4,519 करोड़ के और 31 मार्च, 2000 के अंत तक आपके पास 33,367 करोड़ के सोर्सिस हैं। तो यह विस्तार तो छोटा नहीं है, विस्तार तो बड़ा है लेकिन इस बड़े विस्तार के बावजूद आपको 5000 करोड़ तक के लिए जाना पड़ रहा है और उसके लिए आप बॉण्ड भी निकालेंगे लेकिन बॉण्ड के लिए जो भूमिका आपने दी है, उसमें आपने स्पष्ट कहा है कि उसमें किसी सरकार या बैंक की गारंटी नहीं होगी। अगर गारंटी नहीं होगी तो क्या होगा? आपके बॉण्ड कौन खरीदेगा? एक रुपए का नोट भी अगर जनता लेती है तो वह उसके ऊपर गारंटी लेती है, दो रुपए के नोट पर भी गारंटी लेती है, तो बगैर गारंटी के आप बाजार में कैसे जाएंगे, कैसे आप किसान से बात करेंगे, इस पर भी आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए।

आप अपने आंकड़ों में देख रहे होंगे कि सबसे कम खर्चा आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर नए-नए प्रयोग देहात-देहात में हो रहे हैं, उन पर सबसे कम खर्चा हो रहा है। 31 मार्च, 1998 से 2000 तक सब मदों को मिलाकर आपने कुल खर्चा 42.72 करोड़ का किया है। जहां तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रश्न है, माननीय उपसभापति महोदया, मैं सारे सदन के सामने आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूँ कि यह खर्चा कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए और आपको खाली सरकारी तंत्र के आधार पर ही काम नहीं करना चाहिए। मैं आपके सामने उदाहरण देना चाहता हूँ दाल के क्षेत्र के बारे में। दाल की, दलहन की उपज बढ़े, इस बारे में देश में संतोषजनक काम नहीं हो रहा है और जहां काम हो रहा है वहां पर आपकी कोई भूमिका नहीं है। आपके अधिकारी लोग चाहेंगे तो मैं नाम दे दूंगा लेकिन यह जुड़ जाता है कृषि विभाग से और आप होते हैं दित्त मंत्रालय में। अब इनमें जो समन्वय की कमी है, उसका हम क्या करेंगे? तो आपको इनमें भी थोड़ा सा सामंजस्य बैठाना पड़ेगा।

एक विशेष निवेदन मैं आपसे और करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप उस पर विचार करें कि यह ट्रैक्टर आज किसान के अर्थशास्त्र के खिलाफ हो गया है। आप हजार उसकी तजवीज़ करें लेकिन हमारा किसान ट्रैक्टर का लोन तक चुका नहीं पा रहा है। आप जानते हैं कि आज जीज़ल किस भाव पर मिल रहा है। आप जानते हैं कि किसान ड्राइवर नहीं रख सकता है, ट्रैक्टर पर ड्राइवर रखना उसके लिए मुश्किल है। या तो उसकी बीवी-बच्चे उसे चलाते हैं या उसकी नातिन, पोतियां, बहू-बेटियां उसे चलाती हैं। उसके पास ड्राइवर की तनखाह के पैसे नहीं हैं, ट्रैक्टर की मेंटेनेंस उससे नहीं हो पा रही है, उसके कलपुर्ज महंगे हो गए हैं। किसान ट्रैक्टर का कर्जा चुकाना चाहता है लेकिन नहीं चुका पा रहा है। तो जो कर्जा लेकर उसे चुकाना चाहता है उसको तो लोन नहीं मिल पा रहा और जो कर्जा नहीं चुकाता है और आपका पैसा खा जाता है, उसको लोन मिलता है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर के बारे में जो असंतुलन और विसंगतियां देश में पैदा हो गई हैं, उनके बारे में भी आपके मंत्रालय को गंभीरता से विचार करके कोई रास्ता निकालना चाहिए।

एक निवेदन मैं सदन का मन देखकर कर रहा हूँ, माननीया उपसभापति महोदया के संरक्षण में कि आप इस संशोधन के पास होने के बाद जो उसके नियम-कानून बनाएं तो उनमें एक संशोधन यह भी करें कि बैंक के बोर्ड की कोई भी बैठक पांच सितारा होटल या दिल्ली, मुम्बई जैसे शहरों में कभी नहीं होगी। आप उस गांव में बैठक कीजिए जिसकी आबादी 5,000 से ज्यादा न हो। तब आपको मालूम पड़ेगा कि गांव का जीवन कैसा होता है, वहां संघर्ष कैसा होता है। यदि आप बोर्ड की बैठकें पांच सितारा होटलों में या एयर कंडीशंड चैम्बर में करना शुरू करेंगे तो आप इस देश की कृषि के ~~संशोधन~~ संसाधन नहीं कर पाएंगे। आपको देहात में जाना चाहिए और आप बोर्ड

की बैठकों के बारे में स्पष्ट कर दीजिए कि बोर्ड की बैठकें पांच सितारा होटलों में या एयर कंडीशंड चैम्बर्स में नहीं होंगी, उसके अलावा कहीं और बैठकें करें और हो सके तो गांवों में करें और तब हम कृषि के विकास को आगे ले जा सकेंगे।

मंत्री महोदय, मैं कुल मिलाकर आपकी नीयत पर शक नहीं करता, आप अच्छी नीयत से यह संशोधन विधेयक लाए हैं लेकिन नीयत के साथ-साथ आपका अमल भी अच्छा होना चाहिए और उस पर आपको पूरा सहयोग मिलना चाहिए। अभी हमारे एक साथी द्वारा बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी बात कही गई है। हमारे साथी ने कहा है कि कहां ऐसा न हो कि आप इसका अध्यक्ष मैनेजिंग डायरेक्टर को बना देना चाहते हों। इस व्यवस्था को खत्म कर दीजिएगा। अध्यक्ष जनता का ही रहे, देश का रहे, किसानों का रहे, खेती-बाड़ी वाला रहे और कृषि का मतलब समझे ताकि आप सही मायनों में सही फैसले कर सकें। आप इसको ऑटोनॉमस बनाने जा रहे हैं, बनाना चाहते हैं, इसकी ऑटोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, यह स्वागत योग्य है लेकिन इसमें से लोकतंत्र कहां कम न हो जाए, लोकतंत्र की भावना नष्ट न हो जाए, इसकी पूरी पहरेदारी आपको करनी चाहिए। इसलिए इस प्रावधान को इसमें से निकाल दीजिएगा। महोदय, 19 वर्षों में हम पहली बार विचार कर रहे हैं, 19 वर्षों में पहली बार आपने पीछे मुड़कर देखा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ लेकिन 19 वर्षों के सिंहावलोकन के पश्चात् भी यदि बात अचूरी रह जाती है तो मैं मानता हूँ कि होमवर्क नहीं हुआ है और हड़बड़ाहट में यह बिल तैयार कर लिया गया है। इसमें से हड़बड़ी वाले तत्व को आप निकाल दीजिएगा, जल्दबाजी को निकाल दीजिएगा और जल्दी ही पुख्ता संशोधन और कानून के साथ आप आगे इस काम को बढ़ाइएगा। इसके लिए देश आपको धन्यवाद देगा।

महोदय, मैं मंत्री जी का बहुत आभार मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सदन के माननीय सदस्यों ने, विद्वान सदस्यों ने, हमारे साथियों ने उनके सामने जो सुझाव रखे हैं, उन सुझावों का ये सम्मान करेंगे और उनका मंत्रालय इन सुझावों को अमल में लाने की कृपा करेगा।

माननीय उपसभापति महोदय, मैंने देश में जगह-जगह दो-एक नारे दिए हैं। शायद आपको जानकारी होगी कि "हम दो हमारे दो" का नारा भी मेरा ही दिया हुआ है। आज से 31 साल पहले जब मैं भोपाल में मंत्री था, उस समय मैंने यह नारा दिया था।

श्री संघ प्रिय गीतम : अब आपको यह नारा बदलना पड़ेगा, "मैं एक मेरा एक" करना पड़ेगा।

श्री बालकवि बैरागी : अब मैंने नया नारा दिया है "एक जोड़ा एक संतान"। बेटे, बेटी वाली बात तो खत्म हो गई है क्योंकि हम बेटे के चक्कर में बेटी को पैदा ही नहीं होने देते हैं। फिर कैसे चलेगा काम? मां की कोख को आप कैसे बंद कर सकेंगे? नहीं हो सकेगा। मैं यहां पर इस संशोधन में अपनी ओर से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि एक भावना जरूर ध्यान में रखें और वह भावना है "खेत सुखी खलिहान सुखी तो सारा हिंदुस्तान सुखी"। अगर हमारे खेत और खलिहान सुखी हैं तो सारा हिंदुस्तान सुखी है। हमारे किसान आत्महत्या करने से बचें, उनकी पीढ़ियां खेती की तरफ प्रोत्साहित हों, उनको अपनी उपज के वाजिब मूल्य मिलें, यह कामना करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया।

उपसभापति : अगर कहीं महिला पैदा कर देते हैं तो उसको जगह नहीं देते हैं, किसी जगह रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, रिजर्वेशन मांगना पड़ता है। हम 2-4-6 लोग जो हैं, we flew over the cuckoo's nest पर बाकी महिलाओं की बात मैं कर रही हूँ जो गाँवों में ही रहती हैं।

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat): Madam, I rise to support the National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Bill, 2000. In this amending Bill, I would like to stress on clauses 6 and 19. Of course, clause 26 is also very important. This amending Bill is going to give capital adequacy to NABARD. It will also offer functional autonomy to it. But, so far as the scope of this Bill is concerned, we could see that the Act was enacted in 1981, and, for 19 years, the previous Governments could not amend it. It is this Government which has brought forward this amendment because it has in its mind the interests of rural infrastructure, rural development and the upliftment of our agriculturists. The hon. Minister, who is considered to be the exponent of co-operative activities, has thought it better to bring forward this amending Bill. But, at the same time, I would like to say that the functions of NABARD, in the interest of rural development, will not meet the intended end, unless we put the agricultural policy first. We do not have a specific agricultural policy, and, therefore, we can't think of the welfare of the agriculturists, even though 70% of the population depends on agriculture. Therefore, I urge upon the hon. Minister to consult the Ministry of Agriculture and come up with a National Agriculture Policy. You should decide on that.

Secondly, I would like to stress that the Government must create some infrastructure for irrigation. The agriculturist must be provided with all the facilities. I read just a few days back that a seed which was supplied to Karnataka did not prove to be successful and it was a waste. Today, the agriculturist is facing very many problems.

SHRI BALKAVI BAIRAGI: Similar is the case in Andhra Pradesh.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: In your Madhya Pradesh also, fields have dried up. I am not commenting on that. I would like to say that Andhra Pradesh is on the top, as far as drafting an excellent Cooperative Act is concerned. It is a model Act now. It is a very fine Act. They have drafted it very well.

Madam, the authorised capital of NABARD is going to be raised from Rs. 500 crores to Rs.5,000 crores, as pointed out by many of the hon. Members, and as mentioned in the Statement of Objects and Reasons. But,

4.00 P.M.

so far as Section 19(c) is concerned, there is still a little ambiguity. It says: "Borrow money from Central Government or any other authority or organisation or institution approved by the Board on such terms and conditions as may be agreed." I will be highly obliged if the Minister clarifies the word, 'any other institution.' This is very dangerous. If it is intended to borrow money from any foreign institution or bank, then, I think, the whole idea of independence will be jeopardised by this word. If you are going to borrow, we don't say no. In future, if you are not in a position to repay, then, I think, the whole nation will have to face the hardship. Therefore, I would like to have a clarification from the Minister.

We, and the hon. Minister, know the system of finance and refinance. But with regard to enhancing or increasing the activities of NABARD, so far as the question of self-help groups is concerned, insofar as the district cooperative banks are concerned, so far as the small-scale industries are concerned, so far as the handicraft industries are concerned, have you ever thought of NPAs in the nationalised banks? It is a worst thing and the recovery is not possible. At the same time, if NABARD is going to face the problem of NPAs, then what particular solutions do you have with you? We would like to know on that also. Simultaneously, Madam, the State Cooperative Banks, to whom they refinance, ultimately, lend to the district cooperative banks and cooperative societies. With the introduction of the self-help group system, you are going to mar the growth of the cooperative movement. Just 11 to 20 people get together and say that they have a group which the NABARD is going to finance. But what about the cooperative movement which is going on throughout the nation? Therefore, there will not remain any activity as such to fulfil that particular motive of the cooperative movement. Madam, I would like to submit one more thing. There should be control over the State Cooperative Banks also. But we do not find it. I came across an instance in Gujarat where the Gujarat State Cooperative Bank had created an infrastructure named as the National Institute of Cooperative Management. The hon. Minister will be surprised to know that this trust was registered with the Charity Commissioner whereas more than ten crores of rupees were spent. At the same time, if you look at the trustees, you will be surprised to know that five of its members shall be the permanent trustees of its board in their personal capacity. What is the need of spending Rs.10 crores when it is the property of the Cooperative Bank? Therefore, I would request the hon.

Minister to go for an inquiry into it. These trustees cannot work in a personal or individual capacity. So far as trustees are concerned, there should be *ex-officio* members and also the governmental members. But these members should not be in their personal capacity. Now I come to clause 6 where nine experts have been shown. In the same clause which is given on page 3, it is provided that three directors will be from amongst experts in rural economics, rural development, village and cottage industries, small-scale industries or persons having experience in the working of co-operative banks, regional rural banks or commercial banks or any other matter the special knowledge or professional experience in, which is considered by the Central Government as useful to the National Bank. Out of these nine directors, three are nominated. But when their activities are going to be debarred or discarded is not known. These directors who are from very important fields, I feel that one should have been taken from each field. Then, Madam, I come to the next portion. It says, "Provided that until the assumption of charge by the elected directors under this clause, the Central Government may at any time nominate such number of directors not exceeding four from amongst persons having special knowledge of, and professional experience in agricultural science, technology, economics, banking, cooperatives, law, rural finance, investment accountancy, marketing or any other matter, the special knowledge of, and professional experience in, which would, in the opinion of the Central Government, be useful to the National Bank for carrying out its functions." (Interruptions)... I am speaking only for the first time during this Session. (Interruptions)... Our party has a little time. (Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Did I ring the bell? (Interruptions)..

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: I am sorry if you have taken it. Out of these 14, experts from different fields, they are going to appoint just four. So, nowhere there is a balance of expertise. On this aspect also, I would request the hon. Minister to think of it. Furthermore, I would like to say that this Act is intended for the rural development and the upliftment of the agriculturists. Last year also, on the floor of this House, I spoke about crop insurance for the agriculturists and about those who have insured. I am sorry -- and I am surprised -- being the Chairman of the District Cooperative Bank and Director in the State Cooperative Bank -- to find that after the representation, a special officer from the insurance company was nominated to go into the particular allegation. But, surprisingly, where the crops had failed, where there is not even 50 per cent procurement from the agriculturists, some of the talukas in my district were not granted the crop

insurance amount. In this way, the agriculturists are suffering; the insurance company is not going to pay the interest that is accruing from that particular amount which they have taken as loan for agricultural purposes. Therefore, I would like the hon. Minister to go into this particular matter so that the poor people may get the insurance amount. With these words, I support the Bill. Thank you very much.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Madam, I am not prepared to support this Bill, unless an assurance is given by the Government that there will be a proper management of the banking system. Otherwise, there is no use of passing this Bill and increasing the authorised capital from Rs. 500 crores to Rs. 5,000 crores. When the employees in the banks are eating away the money in the banking sector. The purpose of this Bill is for the promotion and development of agriculture, small-scale and cottage and village industries, for rural development, securing prosperity for the rural areas. The objective is good. But who is getting the benefit? There are three categories of persons who are approaching the banks for loan; first is the agriculturist, the other is the big landlord; and the third is the small farmer. Out of the 70 per cent of rural population, mainly agriculturists, nearly 80-90 per cent are small farmers, but that benefit does not go to them. When they approach the bank, loan is not given to them. If at all any loan is given, they will have to pay 10 per cent or 15 per cent of the loan, as commission to the persons who are sanctioning the loan. If that percentage is not given, the loan is denied to them. But the industrialists and the big landlords are prepared to pay that. After availing of the loan, they do not repay it. Many of the non-performing assets are only from these industrialists and big landlords. I would like to know from the Government whether the Government is prepared to publish the list of persons who have earned crores of rupees and not repaid it? Who are the persons?

If it is published, we will know the true face of this banking sector. While the entire money is given to a few people, thousands and thousands of persons are denied of this benefit. Then, why do you say that it is for the benefit of the agriculturists? How do you say that it is for the development of the agricultural sector and the rural areas? The sorry state of affairs is continuing. I quote one instance. Madam, in Karoor Co-operative Bank, Rs. 68 crores was misappropriated. No action has been taken against any person. But the poor people who are availing of a loan of Rs. 1,000 or Rs. 2,000 or Rs. 5,000, and if they are not able to repay -- it is not a question of not repaying -- the loan amount on account of failure

of crop, their utensils in the house are attached, proceedings are started against them, their utensils are thrown on streets and they are put to a lot of shame. There are instances where some families even committed suicides because of the humiliation that they got from bank authorities. I would like to know whether any action has been taken against such people. Without eradicating all these evils, what is the purpose of giving loans like this? As a matter of fact, the small farmers are not able to repay the loans they have taken. It is not that they are not paying intentionally. It is not that they are not willing to pay the loans that they have taken. The problem is, if at all they get any loan, they get it at an inappropriate time and they do not get loans when required. The result is crop failure. The loan will be given at inappropriate time and the investment made on land will become non-returnable. The result is, poor farmers are not able to repay the debt. But, it is not the case with industrialists and other rich people who avail of very heavy loans, and the same is being diverted and utilised for some other purpose for which it was not intended. So, these are the problems that are being faced by the farmers and poor people.

Your objective to strengthen the NABARD, as a financial institution, is correct. All right. But the purpose is not achieved. It is not meeting the aspirations of rural development. Madam, rural development is not achieved by this. It has been said that there are bottlenecks in the functioning of this institution. You want an autonomous status to this institution. All right. But, I would like to know whether it would satisfy the requirements of the common people and the agriculturists? If it is done, it is okay. There is a request for representation from the small farmers on the Board. After reading the provisions, category-wise, with regard to the Board of Directors, I appeal to the Government that let there be some representation from the farmers on the Board. Let there be a representative from the category of the small farmers on the Board of Directors. It is only those people who can really know the problems of the people and they can be amenable or they can understand the feelings of the real persons who are in need of financial assistance, and that can be voiced in the Board meetings and the real benefit can be given to them. I appeal to the Government to make a provision for representation of small farmers on the Board of Directors. With these words, I conclude. Thank you.

श्री बालासाहेब विखे पाटील : उपसभापति महोदया, मैं सभी सदस्यों का ऋणी हूँ कि उन्होंने इस बिल के सभी पहलुओं में हिस्सा लिया और अपने सुझाव भी दिए...(व्यवधान)...

श्री बालकवि बैरागी : आप अगर ऋणी हैं तो ऋण को चुका भी दीजिए...(व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गौतम : आपके नहीं हैं, आपको कहना पड़ेगा...(व्यवधान)...

श्री बालासाहेब विखे पाटील : उन्होंने कानून के बारे में कहा, बैंक की व्यवस्था के बारे में भी कहा। आप सभी जानते हैं कि नाबार्ड बैंक खुद ही फाइनेंस करती है सीधे फाइनेंस किसी को नहीं करने देती हालांकि इसके लिए को-ऑपरेटिव बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स भी हैं। हमारे मित्र पंचोरी जी ने इनिशियेट किया इसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ हालांकि हमारे बंधु को छोड़कर सबने इसका समर्थन किया है...(व्यवधान)...

उपसभापति : उन्होंने राइडर के साथ समर्थन किया है। मंत्री जी, राइडर लगाकर।

श्री बालासाहेब विखे पाटील : यह बिल इसलिए लाया गया है कि सबको ऋण मिले। मेरे कुछ बोलने से पहले ही कुछ सदस्यों ने जिक्र किया और उपसभापति जी ने भी कहा कि लोग जयानी के समय में महिला की बात भूल जाते हैं। इस संबंध में इतना ही कह सकता हूँ कि जब इनऑगरेशन हो जाएगा तो उसमें हम महिला का भी ध्यान रखेंगे। यह बात अभी लिखित में तो नहीं हो सकती क्योंकि इसके लिए कानून में संशोधन होगा, लोक सभा में जाएगा लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि नोमिनेशन में महिला पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरी बात जो पंचोरी साहब ने कही उस संबंध में मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि जी.एल.सी. का जो 5,700 करोड़ रुपये है, उन्होंने कहा कि वह 6,200 करोड़ रुपये हो चुका है, इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी यही कोशिश है कि सेंट्रल बैंक में इसकी घनराशि दिन-प्रतिदिन बढ़ क्योंकि जैसे-जैसे घनराशि बढ़ेगी वैसे-वैसे अच्छा होगा। अभी तो लोग पैसे की मांग कर रहे हैं हालांकि कमर्शियल बैंक भी रिफाइनेंस देता है, हम इतना ही चाहेंगे कि जो टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, मिडियम टर्म लोन देते हैं वह सब मिलाकर अठारह सालों में आज तक 173910 करोड़ रुपये तक दिया है। लेकिन इससे काम नहीं चलता। अरबन बैंक के बारे में एक सदस्य ने पर्जी भेजी थी उनसे मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस संबंध में हमने एक सर्कुलर भेजा है। अरबन बैंक किसी को कृषि उद्योग के लिए, कृषि के लिए, कृषि उपज के लिए जो ऋण देगा उसे नाबार्ड रिइन्वर्स भी करेगी। इतना ही नहीं इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए नाबार्ड जो खर्च कर रही है हम चाहेंगे कि उसमें भी बढ़ोतरी हो। जैसे-जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे-वैसे बेरोजगारी भी कम होगी, आमदनी का लाभ होगा और जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हम करना चाहते हैं वह भी हो सकेगा। गौतम जी ने एक बात कही कि पहले हम कृषि के सम्मान की बात कहते थे, हम व्यापार मध्यम और नौकरी कनिष्ठ कहते थे। लेकिन आज उलटा हो गया है नौकरी बड़ी हो गई है, व्यापार अपनी जगह पर है और कृषि बिल्कुल सम्मानित नहीं रही, वह इज्जत की बात नहीं कही जाती। लेकिन नाबार्ड और भारत सरकार की यह कोशिश है कि कृषि दुबारा ऊपर जाए जिससे किसानों की इज्जत बढ़, कृषि की उपज हो, कृषि को ठीक दाम मिले, कृषि पैल्यू एडिड के लिए भी हम ऋण देने की सोच रहे हैं। इस संबंध में हमारे सोलंकी साहब ने भी अपनी धिता व्यक्त की। उन्होंने इंचायरी के बारे में कहा, उनकी कठिनाई ठीक है, यह कहने की बात है और मैं गुजरात की ओर भी ध्यान दूंगा। नाबार्ड में हम जो परिवर्तन करना चाहते हैं इसके लिए हमने जो कपूर कमेटी बिठाई थी उसके कुछ नतीजे सामने आए हैं। जिन्हें हम रिकमेंडेशन कहते हैं उन पर दो दिन गौर भी हुआ और उस पर इंटेरेक्शन करके अमल भी किया जाएगा। काफी विस्तार से इसमें नाबार्ड के ऋण को लेकर छोटे उद्योगों के लिए जो कठिनाई पैदा होती है उसका भी जिक्र किया है। जैसे जब कोई

साइक्लोन आता है, कोई सूखा पड़ता है तो उनको उसी हिसाब से सीधा पैसा दिया जाए। इस तरह से इसमें सुधार करने की हम कोशिश कर रहे हैं। किसानों के बारे में आपने दूसरी बात कही है। आपने कहा है कि ऋण लेने में उनको आपत्ति, परेशानी होती है। हमारे यहां कोआपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक हैं और तीसरे निजी बैंक हैं। कोआपरेटिव बैंकों में जब इस तरह की आपत्ति हो सकती है, ऐसी शिकायतें आ सकती हैं, इसका मुझे बहुत दुख है कि कोआपरेटिव में भी रिश्तत की बात चलती है। कमर्शियल बैंक की काफी कम्प्लेंट्स हमारे पास आती हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसानों और आम लोगों को इज्जत मिले। बड़े लोगों की इज्जत करना ठीक बात है लेकिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसीलिए किया गया था कि आम लोगों को इज्जत मिले और इन लोगों को लाभ पहुंचे। इसीलिए यह सब काम इकट्ठा करके नाबार्ड के पास पहुंचा दिया गया। जो श्री बैरागी जी ने बात कही उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि इन बैंकों का नाम ही कृषि विकास बैंक है। भूमि विकास बैंक अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग होता है और उन पर स्टेट का अधिकार होने के कारण उनका नाम भी बदल सकता है लेकिन भारत सरकार ने जो इस बैंक का नाम रखा है, मुझे लगता है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई कन्फ्यूजन और कोई संदेह हो सकता है ऐसा मुझको नहीं लगता है। हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से सीधे गांव के एनजीओज को ऋण मिले। विलेज पंचायत को हम कैसे ऋण पहुंचाएं इस पर विचार चल रहा है। कपूर कमेटी ने सुझाया है कि स्टेट बैंक के अलावा जो जिले में बैंक हैं, इन जिलों में बैंकों के माध्यम से सीधा ऋण दिया जा सकता है। अभी कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि आर.बी.आई. ने डेढ़ प्रतिशत बढ़ाया है। क्योंकि सब जगह ब्याज की दर बढ़ गई है इसलिए इसको बढ़ाना जरूरी था। यह इसलिए जरूरी था क्योंकि आम व्यक्ति मार्केट से बौंड खरीदेगा कुछ और खरीदेगा। लेकिन कोशिश यह हो रही है और भारत सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस तरह का काम कर रही है जिससे किसानों को सही दाम में और कम से कम समय में ऋण मिले। यह भी व्यवस्था की जा रही है कि उनको समय पर लोन मिले। फसल से पहले उनको ऋण मिलना चाहिए। इसके लिए किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड शुरू कर दिए हैं। यह इसलिए शुरू किए हैं कि अगर एक दफा उनका लोन मंजूर हो जाए तो धीरे धीरे जरूरत के वक्त उसको निकाल सके। मेरे गांव में यह कोशिश की गई और 14 प्रतिशत की दर पर जो ऋण था वहां किसानों ने ऐसी कोशिश की जिससे उनको वह एवरेज 10 परसेंट पर मिला। इससे काफी बचत हो रही है। हम चाहते हैं कि भारत में जितने किसान हैं उन सभी को किसान कार्ड मिल जाए। जो इसके लिए पांच हजार रुपये की लिमिट थी वह हमने हटा दी है। गरीब किसान को ऋण मिल सकता है, मीडियम लोगों के लिए भी ऐसी सुविधा अब है। बैंक उनको ऐसी सुविधा देता है। फाइनेंस विभाग द्वारा कृषि कार्ड की सुविधा इन सबके लिए कर दी गई है। इसे बाकी लोग धीरे धीरे अनुभव से स्वीकार कर लेंगे।

अभी यहां पर हम बात कर रहे थे कि एयर कंडीशन में बैठकर बात करते हैं। ससद के दोनों सदन एयर कंडीशंड में बैठकर चर्चा करते हैं, चाहे धूप हो या ठंड हो, कुछ भी हो। लेकिन जो हम यहां एयर कंडीशन हाल में बात करते हैं वह देश हित की बात करते हैं। जिस वर्ग के लिए हम बिल लाते हैं उस वर्ग की हम यहां बात करते हैं। किसानों का बिल लाते हैं तो किसान की बात करते हैं, मजदूरों का बिल लाते हैं तो मजदूरों की बात करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि एयर कंडीशन में बैठने वाले बिल्कुल गलत काम करते हों। हां, यह मैं मानता हूँ कि उनको गांव का अनुभव होना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझाव को हम लागू करें। इसके लिए कभी कभी जिला स्तर पर नाबार्ड बोर्ड की बैठक हो सकती है,

जहाँ पर इन्टरव्यू हो। जरूरी हो तो बड़े गांव में चले जाएं जिससे वहाँ पर लोगों के साथ इन्टरव्यू हो जाए। आपको पता है कि हमारे देश में हर एक जिले में, कुछ जिलों को छोड़कर, नाबार्ड में एक जिला आफिसर, जिला विकास अधिकारी है जो नाबार्ड की इन्फ्रास्ट्रक्चरल ऐक्टिविटीज जो हैं उनकी मानीटरिंग करता है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इन्फर्मेशन टेक्नालाजी के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए नाबार्ड ऋण दे रहा है, वाटर रीड डेवलपमेंट को प्राथमिकता दे रहा है, रूरल रोड डेवलपमेंट को प्राथमिकता दे रहा है। 4.50 हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान है और अभी तक 14.50 हजार करोड़ से ज्यादा इसमें खर्च कर चुके हैं। नाबार्ड ऐसी संस्था है जो गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। आम लोगों के लिए यह काम कर रहा है जिसमें मजदूर भी हैं। उसके लिए किसान होना जरूरी नहीं है। कोई इतना स्किल्ड हो इसकी ट्रेनिंग भी नाबार्ड से कर रहे हैं जो वे खुद देंगे। क्योंकि जैसे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, लघु उद्योग हैं, उसके लिए भी हम नाबार्ड के माध्यम से पांच सौ से पांच हजार करोड़ बढ़ा रहे हैं और बाकी रिसोर्सिज भी मोबिलाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह पहली बार, सोलंकी साहब ने सही कहा कि 18 साल के बाद यह सुधार हो रहा है, लेकिन और भी सुधार करने की जरूरत होगी। सुधार की तो एक प्रक्रिया होती है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि सुधार अभी खत्म हो गया है। यह श्रम सुधार हो या कानून सुधार हो या फिर हमारे अंदर भी कोई स्वाभाविक सुधार करने की जरूरत हो, सुधार की एक प्रक्रिया होती है। यह तो जैसे-जैसे जरूरत होती है या समय की मांग होती है, वैसे-वैसे कानून में बदलाव या सुधार करना जरूरी होता है। इसलिए मैं मानता हूँ, कई लोगों ने मुझसे किसान के बारे में और हमारे गौतम जी ने भी कहा कि किसान का उसमें कोई प्रतिनिधि होगा या कोऑपरेटिव का कैसे आएगा, तो हम इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अभी तो एग्रीकल्चरल इकोनोमिस्ट्स और प्रोफेशनल्स को तो लगा रहे हैं लेकिन साथ ही साथ जो उस वर्ग के लोग हैं वे किसी तरह बोर्ड में आ जाएं और बोर्ड में कोई खास परिवर्तन नहीं किया है, दो ही स्टेट का है जिसका सभी ने स्वागत किया है कि दो राज्य सरकार के प्रतिनिधि बढ़ा दिए हैं। यह काम के लिए है, सुविधा के लिए है, ऐसी बात नहीं कि किसी को टालने के लिए है। यह किसी को टालने के लिए या बढ़ावा देने के लिए नहीं है। ऐसा कोई अंतर नहीं किया है।

हमारे संसद सदस्यों ने और भी कई बातें कही हैं, लेकिन मैं इतना ही चाहूंगा कि नाबार्ड का काम दिन-प्रतिदिन और अच्छा हो और ऐसा आपको समय आने पर पता लगेगा कि जैसे हम कहते हैं कि पीपुल्स फ्रेंडली वैसे ही फॉर्मर्ज फ्रेंडली, किसान का मित्र बन करके नाबार्ड काम करेगा। आम लोगों का मित्र बन कर नाबार्ड काम करेगा। नाबार्ड और आम लोग, किसान और बाकी छोटे उद्योग, कुछ दिन के बाद हम यह चाहेंगे कि दोनों में कोई ऐसा अंतर न रह जाए। हम यह नहीं चाहते कि नाबार्ड और बैंक ऋणकों को लूटें और धन को लूटें, बल्कि दोनों साथ मिल कर चलें। पचास साल से मैं भी सुन रहा हूँ, बचपन से, कि 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। वहाँ से लोग शहर में आकर भूखे रहते हैं और बिल्कुल गंदी जिंदगी जीते हैं। हम यह चाहते हैं कि नाबार्ड के माध्यम से कुछ ऐसा परिवर्तन करें कि जिसके कारण गांवों के लोग गांवों में ही रहें, उनकी आमदनी बढ़े और शहर की आबादी कम होकर गांवों में चली जाए। क्योंकि नाबार्ड के माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट होगी वह गांव के विकास के लिए और आमदनी बढ़ाने के लिए होगी। ग्राहक कौन है, गांव के किसान और गांव के अंदर जो हैं, वही ग्राहक हैं। मिडल क्लास और हायर मिडल क्लास जिसको हम कहते हैं उनकी तो मर्यादा हो गई है। मैं ज्यादा इस विषय में नहीं जाऊंगा, लेकिन बाकी बैंकों के बारे में जो जनरल बात कही गई है और जो कुछ आपत्ति या कुछ सुझाव आए हैं, उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं उनके ऊपर गौर करूंगा।

जहां तक सुधार की जरूरत है या रिश्त की जो बात कही गई है या फिर अन्य जो बातें कही गई हैं, तो हम उसमें कोई आपत्ति नहीं करेंगे...(व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गौतम : क्या लॉग टर्म लोन किसान को दोगे, 25 साल वाला?

श्री बालासाहेब विखे पाटील : गौतम जी, बात सही है और यहां तो प्रावधान किया गया है कि 25 साल ऋण कम से कम दिया जाए, ज्यादा नहीं। हम तो यह कहने वालों में से हैं कि अभी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात, ट्रैक्टर की बात आपने कही है, हम यह भी सोच रहे हैं कि सभी किसानों को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए नई व्यवस्था कैसे करें जिसके कारण उनको कोई असुविधा न हो और किसान को किसी बैंक की रिकवरी या असेसमेंट का या फिर सुइसाइड का शिकार न होना पड़े। किसान या कोई भी ऋण लेने वाला या देने वाला, नाबार्ड के माध्यम से फाइनांस लेने वाला हो तो ज्यादा करके दीर्घकालीन ऋण किसान को दिए जाएं तो इससे मुझ लगता है कि उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं होगी। वह उनके लिए और देश के लिए भी भारी सुविधा होगी। यह आपने जो आशंका की है, What are the other institutions which are likely to be financed? क्योंकि यह विधेयक दोनों इंस्टीट्यूशंस का है, To mobilise other resources and to distribute the loans also. But the other institutions should be relevant to rural development, relevant to agricultural value-added product, relevant to employment, relevant to integrated rural development. अदर इंस्टीट्यूशंस से आपका मतलब यही है, विदेश की बात जो कही है बिल्कुल कानून में यहां सुविधा की है क्योंकि नाबार्ड यह भी काम करे कि विदेशी ऋण जो यहां आता है और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसका फायदा सीधा किसान को पहुंचे। और जब किसान को फायदा पहुंचेगा तो उससे किसान की भी तरक्की हो सकती है। महोदया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात चल रही है और उससे भी उसको सुविधा मिलेगी।

महोदया, किसानों की बात हो तो मैं एक घंटा भी बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बहन जी कह रही हैं कि फिर उन के बिल का क्या होगा। इसलिए मैं उन का भी ध्यान रख रहा हूँ। महोदया, मेरे बारे में माननीय सदस्यों ने जो सहानुभूति के शब्द कहे हैं, पता नहीं मैं कितना उसके लायक हूँ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let me finish the Bill. ...*(Interruptions)*... Raising questions and seeking answers like this will really spoil the mood. Let him finish.

लेकिन मुझ आशा है कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए नाबार्ड काम करेगी। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि ये सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित करें। I shall now put the motion moved by Shri EV Alias Balasaheb Vikhe-Patil to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

[20 December, 2000] RAJYA SABHA

Clauses 2 to 31 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI BALASAHEB VIKHE-PATIL: Madam, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

**THE JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN)
BILL, 2000 - Contd.**

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will now take up the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Bill, 2000. मंत्री जी ने अपना भाषण कल कर दिया था। One thing I have to ask the House. In the Business Advisory Committee, no time was given for discussion on the Bill. I have some names of Members before me. I would like to know the opinion of the House. There are not many Members who want to speak, but, by and large, there is unanimity on the Bill which was needed to be brought for strengthening the protection of children, and it is in the true spirit of the protection of children that definitely, justice should be given to them in a proper manner. So, I would ask the House, "Shall we give one hour for discussion?" We can finish it in one hour. For that, I will have to remove a lot of names, and I will go according to the names given in the list. I have a targeted time of one hour. If there is anything essential that you want to say about the Bill itself, you are welcome to say.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल) : एक घंटे से पहले हो जाय तो कोई बात नहीं।

उपसभापति : अब आप इतने ज्यादा एंथ्यूजियास्टिक मत होइए।

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) : मैडम, कल जिन विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाया गया था क्या वे दूर कर दी गई हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: When she starts, I will tell her. Let me first give time for discussion on the Bill. Misraji is here; I will ask him. The thing is that we have one hour. I would appreciate if you all abide by the time. We have only today and tomorrow. Then there is Friday. After this, we have got Financial Business to finish. The Appropriation Bill is there. There is a Supplementary List of Business which is circulated. So, look into it. I know that you all can speak for hours on the protection of children,

but in the true spirit, and as you have studied the Bill at least last night, if you think there are any suggestions to give, please give them. But if we discuss the protection of children in the entire country and around, then I think we need six or seven hours. So please abide by your time. So, one hour is given.

SHRI RANGANATH MISRA (Orissa): Madam Deputy Chairman, I thank you for allowing me to speak on the subject. I appreciate that it is the Government's obligation to have a municipal supportive legislation to implement the Convention on the Rights of the child.

I congratulate the Minister because she has been able to take up the subject. But I have not been very happy with the Bill as presented. It is well-known to all of us that the law maker, that is, this House and the Lok Sabha, applies its mind at one point of time and once the Bill is transformed into a statute, this House has nothing more to do with it. Thereafter, it comes under the jurisdiction of the court to start interpreting. While this House stops dealing with it, the interpreting authority is entitled to keep on dealing with the matter, as and when it comes. Therefore, it is necessary that the single application by this authority should be done in such a way that there is no loophole in the law. The intention and the purpose for which the law is made should be available in clear terms and the legislation should be such that it serves the purpose for which it is made.

Madam, this House is entitled to a mistake-free draft Bill. I have been able to detect about 40 mistakes. There would, probably, be many more mistakes really appearing in the Bill which require correction. I have, in terms of what transpired yesterday afternoon, handed over a corrected copy--I mean with my suggestions of correction--to the Minister as also to the Law Minister. I don't intend to stand on formalities and I request the House also not to take them on a formal basis. Since these mistakes are continuing, unless these mistakes are corrected, these words may not really convey the meaning that is intended to be brought about and the purpose of the legislation may not be effectively served. There are many places where a comma makes a different meaning, if it is not put at the place where it should be. Therefore, by saying that the mistake of a comma or semi colon or a singular subject with a plural verb or a plural subject with a singular verb is a small or a trivial mistake, you are really overlooking the purpose.

The second thing is with reference to clause 41 which deals with the right to adopt. Yesterday, I had pointed out, and I would like to reiterate, that the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 has a provision in section 11. I will pass on a copy to you, Madam, for your reference. It states:

"In every adoption the following conditions must be complied with:

- (1) "If the adoption is of a son, the adoptive father or mother, by whom the adoption is made, must not have a Hindu son, son's son or son's son's son, whether by legitimate blood relationship or by adoption, living at the time of adoption."

This means that if you have son, you are not entitled to adopt a son. Similarly, there is a provision in the second clause about a daughter. If one has a daughter, he or she is not entitled to adopt a daughter. "This provision applies to Hindus, Jains, Buddhists and Sikhs" This is available at the top portion of the same page.

"This Act applies - (a) to any person, who is a Hindu by religion in any of its forms or developments, including a Virashaiva, a Lingayat or a follower of the Brahmo, Prathana or Arya Samaj; (b) to any person who is a Buddhist, Jain or Sikh by religion, and (c) to any other person who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion." Therefore, this Personal Law applicable to the Hindus does not permit an adoption by a person if he already has a natural or an adopted son. Section 41 (2) of the present legislation also deals with adoption. Therefore, there is an enabling provision for adoption. The question that arises for consideration is this. There is no restriction here, as in the terms of the Adoption Act which has a prohibiting clause. There is no such clause here. You can adopt 10 or 15 or even 20 children at a time. There is no problem that way. So, even if one has a natural son, he is free to adopt a boy. The protection that is available to a Hindu and others, who are already covered by the same provision, does not authorise an adoption, while the present statute seeks to allow adoption. I have two aspects to place for the consideration of the House. One is that, the bar that is there in this Act, applicable to Hindus, is being taken away, and an enabling provision with a contrary scope is being introduced by the proposed legislation. The second one is that there is a social element which one has to consider. When this 1956 Act was adopted, it was felt that the real purpose of the restrictive provision was on

account of the fact that if there is already a son or an adopted son, to adopt another stranger would create disharmony in the family and it would not have the family unit in proper shape. We are passing through difficult times. Social order and discipline that used to be maintained earlier is absent. Social disorder has been spreading, and the family which is the basic natural unit, -- this is recognised everywhere; even the Universal Declaration of Human Rights accept the family as a natural element or the first institution -- would get affected on account of the fact that the combination is not harmonious. If you import another boy from outside, when there is already a natural son or an adopted son, then there is bound to be dispute; there is bound to be chaos and disharmony. Therefore, the real legislative purpose behind the restriction introduced in the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956, was for the purpose that the homogeneity in the family may not be disrupted by introducing an alien element into the family. And that, if you already have a son, then there is no point in introducing another or in duplicating that. If that is taken into consideration, then, it will be easy to understand why such a restrictive provision is beneficial. I personally feel that many of you might have had the occasion to see families getting disrupted on account of almost a similar situation. In the Courts, as a lawyer and judge, I have handled many such cases where families have been disrupted on account of the fact that a stranger has been introduced, and homogeneity has not been developed between the natural son and the adopted son. We have cases where, for example, after marriage, a child is not born. And thinking that the couple is growing and becoming old, they think of adoption. Soon after adoption, a natural son is born and brought into the family. Between the natural son, who is born later, and the son who has been adopted already, there used to be series of disputes. Earlier, it used to be that half of the share used to be given to the adopted son. After a natural son was born, the natural son would get double the share of the adopted son. But this is no more available that way and the system has, therefore, got to be rationalised. If this be the consideration, that the family must be saved, disruption should not come and homogeneity should be maintained, one appreciates the ban; the restriction; and if that was there, that should not be taken away.

So, I submit two aspects. One is that the restrictive provision in the Hindu Law Act should be taken into consideration, as applicable to people to whom it applies, the classes to whom it applies, and that should not be allowed to be taken away by the proposed legislation. The second

[20 December, 2000] RAJYA SABHA

one is: the restrictive provision is socially reasonable one and, therefore, should not be done away with. Both should be maintained. I have suggested an amendment for consideration.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Can you enlighten us on the question of inheritance, Sir?

SHRI RANGANATH MISRA: Now it is equal share.

THE DEPUTY CHAIRMAN: And in the case of other communities, what is the provision?

SHRI RANGANATH MISRA: No adoption is possible. In law, conceptually, there is no adoption, though there have been cases of adoption in recent times. But in a loose sense, we call it an adopted child.

I have suggested an amendment to section 41, for the provision to be made as follows:-

"Such adoption shall be subject to the Personal Law of the adoptive parents."

It is a proviso to section 41(2).

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. That is in the case of others who adopt a child; whatever religion that person is observing, the child will follow the same.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I am sorry, Madam. I think you are pointing to sub-section (6) of section 41, which says:

"(6) The Board may allow a child to be given in adoption

(a) to a single parent, and

(b) to parents to adopt a child of same sex irrespective of the number of living biological sons or daughters."

I think, it is prohibited in the Hindu Adoption Act that you have referred to.

SHRI RANGANATH MISRA: No, no. That is a different thing. I am talking of only section 41(2) which authorises adoption and I want that this provision should be subject to the rider that it will be subject to the personal law of the adoptive parents. If that is accepted, then we have no difficulty. I would request that all of us who are anxious for abandoned children to be supported and their rights to be recognised should consider

it seriously. In fact, when I was working in the Human Rights Commission or even earlier in the court, I was a great supporter of - children and their rights. I feel guilty that this is a country where, fifty years ago, we promised to children certain rights in Articles 24 and 45, but these have not been implemented and children have no capacity to form unions, to demand, to make our activities difficult; otherwise, we would have attended to them long before; and now, fifty years have gone but we have not been able to do that. Therefore, I am anxious that this should be done and we should comply with the international agreement through supporting legislations. But this should not be the way. And I am not used to a legislation that has forty defects, and each of these defects becomes a part of the law and cannot be corrected, and if it is taken out before a court, the court is bound to make a comment about it. Why should we exhibit such conduct is also a matter of consideration. I did not propose 41 or 50 amendments and each one to be pointed out because I expected that the Minister would present a Bill which would read English. I remember of a case, in 1933, when an adoption dispute was taken to the Privy Council. A local lawyer—because there was a lot of evidence on facts—had gone to brief the barrister there. After the case was disposed of—it is AIR-1933/Privy Council, probably, page 214 or 114. It is a case of adoption between two perfect families. The Solicitor charged hundred pounds to render the brief of instructions into King's English. That was a special item in the Bill of Costs. Hundred pounds for the English briefing to be translated into King's English. The lawyer who had gone there, appeared before the Master and raised objections. Twenty pounds were given above the hundred pounds for raising a frivolous objection because what was originally read was not really English. So, this is a case of that type. The Bill placed before us will require assistance to make meaning out of it. We would be unnecessarily called upon to have an additional, unnecessary, exercise. This should not repeat. We have a draftsman; we have a Ministry; we have the system. Therefore, this specimen should not be available to be redone before the House. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It will be much better if the Law Minister, who is here, clarifies this. Then, we can finish the Bill sooner. I will just tell him, in brief, about what happened yesterday. The Bill was brought, and Mr. Ranganath Misra and some others said that there were certain mistakes in the Bill. He has referred to it before you. But he also said that there were certain other mistakes in the language which could change the total meaning of it. That is why, if you could explain it as to what it is, then

[20 December, 2000] RAJYA SABHA

it will be easy. We had before us, earlier, another Bill on Narcotics, where we had the same kind of problem, because once it becomes an Act, it becomes difficult to change it. So, the Minister of Finance who was piloting it, accepted it. ...(Interruptions)... Yes; he was there. Shri Balkaviji pointed out those mistakes. There was a difference between the English and the Hindi versions of the Bill. So, that was ratified later, on our pointing it out.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND MINISTER OF SHIPPING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I will just refer to the principal points which the hon. Member has made, with his very wide experience, as far as the law is concerned. I have also had the opportunity of discussing this subject with the hon. Minister. The point which has been made is that we have provided for adoption under section 41 of this Act. This adoption which has been provided for, and the scheme of adoption which has been provided for, may run contrary to the Hindu (Adoption and Maintenance) Act, particularly the provisions of section 11(vi).

Under the Hindu (Adoption and Maintenance) Act, the restriction is this was a restriction considered appropriate in 1956 if you had a son of your own, or a grandson of your own, you could not adopt another son because they, probably, felt at the time when the Bill was drafted, that the new son who was adopted, even after adoption, may remain a neglected child in the family, and may not get fair justice. That, probably, was the reason. Similarly, a provision was there that if you already had a daughter or a granddaughter, then you are barred from adopting daughters. So, that is as far as the Law of Adoption is concerned. That law is applicable only to those who are Hindus, Jains, Buddhists, to whom this law is applicable.

Now, this legislation which has been brought is a social legislation, with a social purpose, and does not deal with a primary emphasis on adoption. The primary emphasis of this is that, we have lakhs and lakhs of abandoned, neglected and orphaned children in this country. In every city, you have street children; you have children in orphanages. Therefore, there has to be some scheme under which rehabilitation of those children can take place.

Section 40 of this Act mentions, "The rehabilitation and social reintegration of a child shall begin during the stay of a child in a children's home or special home.." --So, you create these institutions-- "...and the rehabilitation and social reintegration of the child shall be carried out

alternatively by (1) adoption, (2) foster care, (3) sponsorship, and, (4) sending a child to an after-care organisation." Therefore, you work for the integration of the child with the society by these four methods, that is, adoption, foster care, sponsorship and sending him to an after-care organisation.

Now, as far as the adoption is concerned, they say, "...in the case of adoption, where a child lives with the family itself, becomes a member of the family. The primary responsibility for providing care and protection to children shall be that of the family." Then, the method of adoption is mentioned and then the restrictions are mentioned, mentioning how do you adopt. No child shall be offered for adoption unless two members of the committee declare that the child is legally through for placement as an abandoned child, and then it says, "The board may allow children to be given in adoption to a single parent," which is contrary to the scheme of the 1956 Act "and to parents to adopt a child of the same sex, irrespective of the number of living biological sons and daughters." So, we are now trying to consciously make a departure from the 1956 law. The reason being, that this law has nothing to do with the religion, either of the child or of the parent. This law is not a personal law. This law has nothing to do with religion.

This law has something to do with the social purpose. The social purpose being that, millions of abandoned children are neglected children or orphaned children, and they must be picked up, and either sent to the homes or be sponsored by well to do people or even be adopted into the families of those affluent people. This law is intended to encourage people, who may be well-off economically and socially, who have the resources. They may have a house, they may have children; and, yet, they agree and say, "To pursue a social purpose, we must either sponsor one child or take one child into adoption and develop the child, grow up the child, as a member of our own family." Therefore, this is a special legislation for rehabilitation of these neglected children.

The former Chief Justice, Misraji would bear out that the law has always been well laid out, that whenever there is a need for a special category, a special law is created. Then, it is that special law which will apply. Most of these children would be those, we are not even aware of what the religion of these children would be, because these children are orphaned, these children, maybe, immediately after the birth, had been left on the roads and in some places, and their religion is not known. Their

5.00 P.M.

religion will not act as a bar because it may not even be known. The parents' religion also will not act as a bar. What is being suggested is, to pursue that social purpose, to encourage well to do people to adopt these children or sponsor these children, you must either sponsor them or you can even adopt them into your families.

So, this special law will have the effect, in the case of these category of children, that is, orphaned, neglected, abused, children, of overriding the general law, which is the 1956 law. So, if there is any person who is to be adopted, who is not in the category of orphaned or abandoned or neglected or abused, then the original law will apply; but, for this category, if, through these institutions, somebody is to be sponsored or adopted, this special law will apply. This special law will defy the religion of the child and it will defy the religion of the parents, and, therefore, this law itself will apply.

I would request Justice Misra to consider this point that in view of the special legislation, and the social purpose of this legislation, the amendment, the suggestion, may not really be pursued; and it is not even necessary to pursue the suggestion, to say that in whichever family you are adopted, you will follow the religion of the parents because this law has nothing to do, really, even with the customary adoption law. It has nothing to do with religion. It has something to do with rehabilitation of orphaned and neglected children and, therefore, for these category of children, the 1956 law will not apply. *(Interruptions)*

The second point which has been raised -- it is a general point -- that there are certain drafting mistakes, etc. Though the specific details have been given, I have been trying to compare the list which was given in the other House. The hon. Minister also went through the entire list which is with the hon. Members. If there is anything specific, the hon. Minister could go into those questions. But what was given in the other House, it was discussed at length and it was found that really there was no inconsistency because a large number of amendments really related to the use of word 'the' and some related to replacing it with a more suitable phrase. But the tenor of each of those clauses where those words have been used substantially is not any different whether those words are there or not. I would request the hon. Members to consider if any such areas where the use of a particular phrase is creating a different emphasis as such.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Before me there is a notice of amendment by Shri Ranganath Misra that at page which says : 12, after line 25, the following proviso be inserted, namely:-

"Provided that such adoption shall be subject to the personal law of the adoptive parents."

This is being circulated. . *(Interruptions)*... If you want clarification, then it should not be in this disorderly manner. *(Interruptions)*... Please listen to me. *(Interruptions)*... If you want that this Bill is discussed, then let us discuss it in a proper manner. You make your speeches and then let the Minister reply. If you say that after your clarifications are finished and you are going to pass the Bill without discussion, then fine, I will allow you at this stage. Otherwise, I will call the next speaker and accordingly others.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPLOYMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI) : Madam, *(Interruptions)*...

SHRI FALI S. NARIMAN (Nominated): Madam, amendments can be taken up a little later after opinions are discussed. Otherwise, we will have to vote on it without everybody knowing it. *(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: The amendment will come when the concerned clause will come. . *(Interruptions)*... Why I read it out because the Law Minister is here. If he wants to make any clarification about it, then it could be taken into consideration.

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Madam, . *(Interruptions)*... Madam, I would request that Mr. Nariman be asked to speak. *(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let the Minister speak. *(Interruptions)*...

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Mr. Nariman may be asked to give his opinion also as a jurist since it is a technical-legal matter for which the Law Minister has taken time off. Since legal questions are being asked, perhaps Mr. Nariman could also ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Nariman's name is there. *(Interruptions)*... If you want to speak *(Interruptions)*...

SHRI FALI S. NARIMAN : Madam, I will take only three or four minutes on this main question. My only request to the hon. Members is to consider this that adoption in this Bill is as a measure of rehabilitation of

[20 December, 2000] RAJYA SABHA

orphaned, abandoned, neglected or abused children. This is not, and is not, intended to be a general law of adoption. This Bill relates to children. This is very important. I recollect, Madam Deputy Chairperson, that I gave evidence here more than 25 years ago before a Select Committee of Parliament on the Adoption of Children Bill, 1972. It was not passed although it was only enabling. Therefore, all our views with regard to adoption have to be slightly kept aside for the purpose of this Bill. It does not apply to all children in the first place. It only applies to certain categories of children who need rehabilitation. The second important thing is that clause 41 (6) to which an amendment is sought is only enabling because it says, "the Board may allow a child to be given in adoption." Now, whether it may allow having regard to the personal law, or it may not allow having regard to the personal law is a matter on which the Board would have to take a decision in each individual case. I would respectfully suggest - Justice Misra may also kindly consider it -- that since there is already power with the State Governments to issue guidelines under clause 41 (3) -- clause 41(3) expressly this -- perhaps the Central Government should indicate to the State Governments to issue an appropriate guideline to the Board emphasising that, "adoption," is a measure of rehabilitation, that it should be made truly effective to enable any adopted child to enjoy the social rights and privileges in the adoptive family without any discrimination, bearing in mind all aspects of the personal law of the adoptive family, without interference with the religious rights and customs of the family into which the particular orphan or destitute child is given in adoption.

Madam, if this is followed, I do not think we will have any difficulty at all, because there are a lot of people who like the Parsis; have no law of adoption. When we say that we adopt so and so, it has no legal effect at all. Therefore, the important thing is, this law is intended really to rehabilitate the child. The Board will consider whether there is any legal impediment, and, after considering it, come to a conclusion whether it will allow it or it will not allow it. We cannot generalise. May I only draw attention to the fact that the International Convention on the Rights of the Child, Article 20 and 21, expressly states that the State parties -- we are a State party to the convention -- shall, in accordance with their national laws, ensure alternative care for such a child, and such care, includes "adoption". So, the International Convention does not prescribe that we should override our laws at all, in the first place. That is a matter of intention. In individual cases, whether or not a particular abandoned child

should or should not be given to a particular family depends on the circumstances of that family, the personal law of that family, what happens in that family, whether that particular son is settled abroad and is very well cared for, etc. In each event, it may or not. Therefore, there is no question of overriding anybody's law or not overriding anybody's law. It all depends on the facts of each case, and I would respectfully suggest that if a suitable guideline is framed with regard to not over-riding any personal law -- because that creates a great deal of problems all round -- I would request the hon. Member who has moved the amendment to consider whether he would like to insist on it.

SHRI ADHIK SHIRODKAR (Maharashtra) : Madam...

THE DEPUTY CHAIRMAN Shall we start the discussion?

SHRI ADHIK SHIRODKAR: One minute, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I want an assurance from the House. I will permit all the legal luminaries to give an opinion on this, provided the House passes it without discussion. If the House is again going to have one hour or two hours of discussion, then we might as well go in a proper manner and not in a haphazard way.

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Certain legal points have been raised and three very eminent legal luminaries have also made their contribution. There are other Members who are also lawyers. So, I think you should devote some time for the discussion, -- it is left to -- about an hour or so, so that the Members can speak. But I entirely agree with you that the discussion should take place in an orderly manner so that the members can make their contribution.

SHRI R. MARGABANDU: Madam, I have only one clarification to seek.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am sorry, Mr. Margabandu, if I call you, I have to call Mr. Ram Jethmalani and others. Please sit down. Take your seat, please. I had already called Mr. Ranganath Misra's name first. He was not speaking out of context. He was speaking in his original position. So, that is it. Now, I will call Shrimati Savita Sharda. She is not present. Shrimati Bharati Ray.

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY (West Bengal): Madam, I will be as brief as I can. This is a very interesting Bill and a very significant Bill. I very much appreciate the purpose, that is, to deal with the subject with sympathy, empathy, sensitivity and imagination. In that way, I support and I welcome the Bill. Particularly, I like two clauses. Clause 21 is very imaginative, really, and it prohibits the publication of the name and address of the juvenile in conflict with law. Anonymity will, certainly, help the process of resocialisation. I like clause 60 which, on the one hand, makes it obligatory for the affluent parents to pay for the maintenance of the child in a special home and, on the other hand, offers financial assistance to the indigent parents for the journeys made to take the children back and forth. I also support the association and recognition of the village panchayats, Zilla Parishads and Municipal Corporations as the local authority in respect of juvenile justice and protection.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) in the Chair]

And, yet, Sir, I have one or two comments to make. While the Bill deals with the care of juveniles, it ignores the point why they are so. No child is a born criminal. It becomes one. It is the lack of economic security, lack of education, training, work as a child labour or a bonded labour or a municipal manual scavenger and lack of nutrition that makes criminals out of children in this country. I will not go into statistics. Sir, 11 million children are on the streets; four lakhs out of nine lakhs prostitutes are minor girls. As the hon. Minister knows, every third case of rape is of a minor girl. If the Government pays some attention to grapple with these problems to resolve them, we will, probably, grasp the intensity of the anguish of all victimised children. Why do I make this point? It may sound irrelevant. I make this point because it becomes clear when you look at the actual provisions of this Bill. What it says? We need to pay more attention to those forces and to those people who instigate children to become criminals. There is a proverb in Bengal. It means, you water the branches and not the roots. You see clauses 23, 24 and 25. Those who are in charge and control of the children, if they assault or cause mental anguish and things like that or wilfully neglected, What are you doing? You are giving punishment for only 6 six months! Employment of juvenile children for begging, your maximum punishment is only 3 years! Maximum penalty for giving intoxicated liquor and subs drugs is only for three years! Abuse of children at home is increasing daily. We know of sexual exploitation of minor girls within the four walls of the home. Begging,

unfortunately, has, almost, become a profession, a business with a host of middlemen charging commission, and a number of anti-socials with networks over huge areas. There is a racket of masterminds operating with a vicious nexus between begging, criminal activity and drug peddling. The situation is even worse. (Time-bell) Sir, only two minutes. As you know, I do not speak for long. Sir, it is worse than the Oliver Twist scenario. These people are the real criminals. And, therefore, they must be given more stringent punishment.

I will complete in two minutes. I am not a lawyer, but I am a mother. Therefore, I understand the problem that Justice Misra has pointed out. Suppose I have a son. I know the purpose is good; it is an enabling clause. But, I wonder whether anybody will adopt a son or a daughter when one has a son and a daughter and grandchildren only for philanthropic reasons. I would argue that we can adopt children for other uses which I need not spell out. The other uses are such as exploiting, bonded labour, employment, selling and so on and so forth. Therefore, this enabling clause - whatever may be the purpose and however good it may be -- should be reconsidered because this may, by trying to help them, end up in giving them further troubles and further problems.

Lastly, chapter II deals with the Juvenile Justice Board. Hon. Minister has also suggested Child Welfare Committee. Excellent! In both of them, you have suggested women. But there is no mention of a vocational trainer or a psychiatrist or an educationist, to listen to the unheard voices, to detect the particular flairs of individuals, and to try to understand them. Therefore, Madam, please consider these points also.

SOME HON. MEMBERS: Not Madam, but Sir!

PROFESSOR (SHRIMATI) BHARATI RAY: Yes. I am addressing Madam, through you, Mr. Vice-Chairman, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I will accept the confusion. Now, Shrimati Vanga Geetha. Madam, you have three minutes. Please remember, after this, we have to sit up to almost 8.30 p.m.

SHRIMATI VANGA GEETHA (Andhra Pradesh): Sir, I support this Bill. It is a well-intentioned Bill. It is a good Bill. I am very grateful to the hon. Minister because it is only due to her enthusiastic efforts that this Bill has come. This Bill will change the lifestyle of the street children, who need care and protection. This Bill seeks to replace the Juvenile Justice

Act, 1968. The enactment has two parts -- the first part deals with juvenile offenders; and the second part deals with juvenile children who deserve care and protection. The question is not of the enactment of a law, but care is necessary while implementing the law. We have juvenile homes in different parts of our country. These homes are meant for providing care and protection. But, unfortunately, they fail to fulfil their duty to safeguard the interests of the children. Sometimes, the children in the shelter homes undergo mental and physical torture; and, sometimes, they just run away from the shelter homes. So, it should be rectified. The United Nations has given consideration to the personnel who will administer the law. The personnel should be qualified and should include sufficient number of specialists, such as educators, voluntary instructors, councillors, social workers, psychiatrists, psychologists. These things are very necessary. If you don't take them into consideration, the enactment will be of no value at all. The administration should be careful in the selection and recruitment of personnel of every grade. I think, the Bill takes good care of it. The children are suffering because of two problems in our country -- one is the poverty; and the second is the urbanisation. Because of poverty, the children are committing crimes. So, they are put in the jails as juvenile criminals. The second is the urbanisation. Because of urban affluence, they are committing crimes. However, many a time, they escape. For treatment of this abnormality, social justice and empowerment is required. The juvenile is in conflict with the law because of poverty in our country. So, when they are put in the juvenile homes, they should be treated properly. They should be allowed to earn while they learn. Let them be put into the mainstream. It is the beginning of the first step in that direction. If they are given proper care, affection and love, many of these crimes would be avoided. The Statement of Objects and Reasons provides for involvement of voluntary organizations. The role of voluntary organizations has not been well-defined in this Bill. Voluntary organisations should be assigned sufficient role. There should be a sincere monitoring of the activities of these organizations. Juvenile Justice police units should not be kept as a part of the present police set up. They should have a totally different approach through gender and child sensitisation. The Juvenile Justice Board and Child Welfare Committees proposed to be set up should have more community involvement.

Lastly, the Bill provides for setting up of Committees at the district level. My request to the hon. Minister is : If Committees at the taluq level and at block level are set up, then, it would be useful.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Please conclude. You have already taken your Party's time.

SHRIMATI VANGA GEETHA : I am concluding. I hope that the Government will put them in the mainstream and make them gentlemen again.

Once again, I congratulate the hon. Minister for earning a very good name in the country for showing a genuine concern towards animals. I think, only a person like her could have brought forth this type of a Bill. This Bill has been brought forth for the purpose of providing proper care and protection to the juvenile children.

On behalf of the Telugu Desam Party and on my own behalf, I support this Bill. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Mrs. Saroj Dubey, you have two minutes.

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) : सर, दो मिनट में क्या बोलूंगी?

SHRI PREM CHAND GUPTA: How can she finish her speech in two minutes? ... (Interruptions)... Please give her more time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): The time has been allotted Party-wise. ... (Interruptions)... Why are you creating a conflict between me and her?

श्रीमती सरोज दुबे : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 जो सदन में लाया गया है, यह एक अच्छा कदम है। लेकिन इस की बहुत सराहना इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि यह व्यावहारिकता से बहुत दूर है।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने कल बताया था कि इस विधेयक की तैयारी में उन्होंने न्यायविद् और पुलिस अधिकारियों से भी सलाह ली थी, लेकिन उन्होंने उन संगठनों से सलाह नहीं की जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और न महिला सांसदों तक से विचार विमर्श किया। इसलिए इस में कमी रह गई है जिस की ओर माननीय न्यायमूर्ति मिश्र जी ने भी इंगित किया है।

महोदय, आप जानते हैं कि देश में तमाम तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे मजदूरी में अनाथ हो जाते हैं, कुछ बच्चे गरीबी के कारण सड़क पर घूमते रहते हैं और कुछ बच्चों को असामाजिक तत्व और माफिया ले जाते हैं और उन से भीख मंगवाते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मंत्री जी ने इस तरह के बच्चों का वर्गीकरण कर के अध्ययन नहीं किया है। महोदय, कुछ बच्चों को इस देश में एक घूंट दूध नहीं मिलता और बीमारी के समय एक गोली तक नहीं मिलती, उन बच्चों के लिए किस तरह से यह कानून बनाया गया है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। माननीय मंत्री जी, इस में जरूरतमंद बच्चों के संबंध में, किशोरों के

संबंध में सक्षम प्राधिकारी का जिफ्र किया गया है और यह सक्षम प्राधिकारी किसी भी एडॉप्शन के मामले में किसी को योग्य संस्था का प्रमाण दे सकता है और किसी को भी योग्य व्यक्ति का प्रमाण दे सकता है कि वह सामाजिक कार्यकर्ता है या योग्य व्यक्ति है। माननीय मंत्री जी ने इस बारे में कोई गाइडलाइंस नहीं दी हैं। अब यह सक्षम अधिकारी खुद सक्षम नहीं है, अच्छा अधिकारी नहीं है तो अगर वह किसी भी व्यक्ति या किसी स्वैच्छिक संगठन को सक्षमता का प्रमाण दे देगा और बच्चों का व्यापार शुरू हो जाएगा। महोदय, इस तरह से संस्थाओं को छूट दे दी गयी तो इन बच्चों पर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अत्याचार शुरू हो जाएगा। महोदय, मैं ने इस में एक जगह देखा है कि राज्यों को एडॉप्शन के मामले में खुद कानून बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए छूट दी गयी है। इस बारे में भी मेरा एक सुझाव है कि हर राज्य में अलग-अलग तरह के विचार की सरकार होती है। इसलिए केन्द्र सरकार को चाहिए कि उन को एक गाइडलाइंस दे दे ताकि पूरे देश में बच्चों से संबंधित और किशोरों से संबंधित जो कानून बने उन में समरूपता हो ताकि हर जगह अलग-अलग तरह का बिखराव न होने पाए। महोदय, राज्यों को इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए और इस बारे में उन को गाइडलाइंस जरूर दी जानी चाहिए। इस के अलावा मैं मंत्री जी से कहूंगी कि बच्चों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं कि आज बच्चे सड़क पर घूमते हैं। दिल्ली की सड़कों पर ही आप देखें तो ये बच्चे गाड़ी पोंछ रहे हैं, उन्हें विकलांग बनाकर उन से भीख मंगवाई जाती है, औरतें छोटे बच्चों को गोद में लेकर भीख मांग रही हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Madam, that is why this Bill has been brought forth here.

श्रीमती सरोज दुबे : मंत्री जी, क्या इस तरह के बच्चों के बारे में आप ने कोई सर्वे करवाया है? इन बच्चों का कैसे सुधार होगा, यह भी मंत्री जी को बताना चाहिए। और जो सक्षम अधिकारी हैं, उनको बच्चों के बारे में पूरी मनोवैज्ञानिक बातें मालूम हैं या नहीं, यह भी देखना चाहिए। इन सारी बातों की इस बिल में कमी है, जिनको इन्हें पूरा करना चाहिए।

इसके साथ ही साथ मैंने बच्चों का व्यापार करने के बारे में जो बात कही थी, वह बहुत गंभीर है। ...**(समय की घंटी)**... मैं दो मिनट में अपनी सारी बातों को कह नहीं पा रही, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। मैं केवल एक और बात कहना चाहती हूँ कि बच्चों का बड़ा भारी घंघा चल रहा है। आप जानते हैं कि अरब कंट्रीज में छोटे-छोटे बच्चों को ले जाकर ऊंट पर बांधा जाता है, लड़कियों के साथ डोमेस्टिक वॉयलेंस हो रहा है। होटलों में या घरों में जो काम करती हैं, उनके साथ डोमेस्टिक वॉयलेंस हो रहे हैं और यह जो किशोरों के एडॉप्शन की बात है, वैसे तो मिश्र जी ने सारी बातें बता दी हैं, मैं उनका समर्थन करते हुए कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह से एडॉप्शन होता रहा तो घर में आपस में ही इतने झगड़े शुरू हो जाएंगे कि किसी परिवार में सुख-शांति नहीं रह पाएगी। इसलिए इस बिल पर बहुत व्यापक विचार करने की जरूरत है, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे एक बार पुनः सलाह लेने की जरूरत है ताकि यह विधेयक व्यावहारिक हो सके और इस देश में जो लाखों-करोड़ों की संख्या में बच्चे लड़प रहे हैं, जो अशिक्षा और अभाव में पल रहे हैं, जो गांव से भाग रहे हैं, जो अत्याचार सह रहे हैं, उनको कुछ राहत मिल सके और यह किशोर न्याय विधेयक बच्चों के लिए राहत का काम कर सके, उन्हें सुनहरा भविष्य दे सके और बच्चों को सामाजिक सम्मान दे सके। इसलिए इसमें सुधारों की जरूरत है और मेरी तो यह राय है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए और एक बार व्यापक रूप से विचार होने के बाद ही इसे आना चाहिए वरना इस पर किसी कोर्ट में स्टे हो

जाएगा, यह बिल जहाँ का तहाँ रह जाएगा और जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है, वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा और हमारे भारत का जो बचपन अब सिसक रहा है वह अपने भी सिमसका रहेगा, उसमें कोई सुधार नहीं होगा। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I would like to request the hon. Members to be brief and avoid repetition. It is an accepted position that there is inhumanity, ill-treatment and all that to the children. In order to avoid all these things, this Bill is being brought. So, referring to these things will not add to the discussion. It will only be a repetition without any purposeful outcome. I will request you to restrict to the Bill itself. Now, Shrimati Bimba Raikar. You have got three minutes.

SHRIMATI BIMBA RAIKAR (Karnataka): Sir, India is a very big country and it has got a huge population. So many problems have been created only because of huge population. One main problem is poverty and unemployment. Because of this poverty, illiteracy and ill-health is there. In a family where the head of the family is the father, when he develops bad habits, vices, the family is broken, and the wife, the mother of the children, cannot take care of the children and they go astray and go to the roads. This type of children are called orphans and destitutes. I want to know from the hon. Minister whether this Bill is only for the offenders or whether this Bill is also for the orphans and destitutes. If we only think of the offenders, then what about other children, who are mentally and physically handicapped, who are orphans and destitutes. What I feel is that there should not be any discrimination among the physically and mentally handicapped children, destitutes and orphans. So, the assessment of juvenility should be based on the recommendations of Justice Krishna Iyer Commission, that is, the code of rights of children. Madam, if we just think in terms of this code, in Karnataka, we have got only seven types of offenders, whereas, over 3000 orphans and destitutes are there. If you are thinking only about the seven offenders, what about the other 3,000 children? I would like to say that our Government is taking care of these children by spending about Rs.800/- to Rs.700/- per month, and whatever help we are getting from the Centre is insufficient. I think, the Centre is giving Rs.350/- or so. It is very difficult to run the institutions where the children are staying, with such a small amount. So, the Government has to think of giving more funds. I request that more funds should be given to these institutions.

You must also think of constructing buildings. Where these institutions are running, the buildings are nearly hundred years old.

[20 December, 2000] RAJYA SABHA

Whenever the inspectors from the Centre come and inspect them, they say that the building is like this, and they pass all sorts of remarks. So, when the Centre thinks of the institutions, it has to think of the old buildings also. The Centre should give more funds to construct buildings.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Please conclude.

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Sir, the maintenance of buildings must be properly done. Sufficient provision should be made for paying salaries to the staff.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Madam, these are matters of details; that will be worked out. Let us go to the broad concept of the Bill.

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: No, Sir. Since we are running these institutions, we know how difficult it is to run them. When parents come and leave the children in the institutions, we can't say 'no' to them; that is why, we have to take care of the children, and the Government has to take care of the funds. It is very difficult to run an institution with insufficient money. I request the Minister, through you, Sir, to take care of the funds. She must think of the rehabilitation of children so that they can stand on their own feet. Sir, I don't wish to say anything about adoption because it is a legal matter. I only want to say that in our institutions, people come and ask for children, and only those who have no children come and ask, and those who have got sons, daughters and grand-daughters, would not come to the institution asking for a child. It is a social adoption. There also, we have to take care that those who are taking the children must treat the children properly. In some cases, they have taken the children, but they are using them for their household work. So, we have to think about that matter and give more funds for adoption.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I can't help it.

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: With these words, I support the Bill and I thank the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Thank you very much. Shri C.P. Thirunavukkarasu. Your time is two minutes.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): Sir, in Clause 32, it is stated:

"Any child in need of care and protection may be produced before the Committee by one of the following persons :-

- (i) a police officer or special juvenile police unit or a designated police officer, public servant, voluntary social worker and the child himself;
- (ii) any public servant;
- (iii) childline, a registered voluntary organisation or an agency as may be recognised by the State Government;
- (iv) any social worker or a public-spirited citizen authorised by the State Government; or
- (v) by the child himself."

If the child himself appears before the Committee, his welfare can be taken care of by the Committee itself. My submission is this. If the child who surrenders before the Committee, is neither an abandoned child nor a neglected child nor an orphan, but is not willing to go anywhere and appeals to the Committee, "You please take care of me." He is neither an orphan, nor an abandoned child, nor a neglected child.

I want to make another submission. In Clause 41(5), it is stated:

"No child shall be offered for adoption."

In Sub-clause 41(5)(b), it is stated:

"Till the two months period for reconsideration by the parent is over in the case of surrendered children."

The Committee has to consult the parents whether they are willing to give their child. If he himself surrenders before the Committee, the parents' consent has to be taken into consideration. That is why, as pointed out by Mr. Ranganath Misra, "The Board may allow a child to be given in adoption-

- (a) to a single parent, and
- (b) to parents to adopt a child of same sex irrespective of the number of living biological sons or daughters."

If the child voluntarily surrenders before the Committee and if he is a Hindu, under those circumstances, it can't be said that he does not have any caste and that he has no religion. As far as the surrendered child is concerned, he is having a caste; he is a Hindu. Under these circumstances, the Hindu Adoption and Maintenance Act is applicable to that particular person. If a person is adopted by virtue of the provisions of section 6 of the Act, whether he will have a right to the property of the adopted father and mother is not spelt out clearly. That has to be spelt out clearly. If it is not done, many litigations may arise tomorrow between a person adopted under section 6 of the Act and the natural son of the family. Unless it is clarified, we cannot come to a definite conclusion. It was pointed out in this House that it could be left to the States, when the rules would be framed. With great respect, I submit that every State will frame a different sort of rules. To incorporate all these things into the rules, we can add a proviso, as suggested by Mr. Misra, "provided such adoption will be subject to the personal law of the adoptive parents". If such a provision is there, it will be more convenient and there will not be any further litigation over that issue. The Board may allow the child to be given in adoption. But, as far as the male is concerned, it will create a lot of problems. If you add a proviso to that effect, every problem will be solved.

I want to say two more things with respect to this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): You please conclude. You have already taken more than two minutes.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: Sir, I am talking only about the Bill.

In clause 12 (1) of the Bill it is stated:

"When any person accused of a bailable or non-bailable offence, and apparently a juvenile, is arrested or detained or appears or is brought before a Board, such person shall, notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 or in any other law for the time being in force, be released on bail with or without surety but he shall not be so released if there appear reasonable grounds for believing that the release...."

According to clause 12(1), the power was given only to the Magistrate to release the person brought before him. If you look at clause 12(2), you will find that when such person having been arrested is not released on bail under sub-clause

(1) by the officer in charge of the police station, such officer shall cause him to be kept in custody and may be released on bail. According to clause 12(1), only the Magistrate is competent to release him on bail. I am unable to understand why clause 12(2) has been incorporated. It is as if the police officer is to arrest him and he is entitled to bail. It is totally redundant and the clause, as it is, should be omitted.

Then, in clause 27, it is stated that the offences punishable under sections 23, 24, 25 and 26 shall be cognizable. But in the marginal note it has been mentioned as "Special offences". In the marginal note also it should be mentioned as "Cognizable offences" and not as "Special offences". In all other Acts also this has been mentioned as "Cognizable offences" and not as "Special offences".

There are other anomalies in this Bill. They have to be removed by the Government.

As far as Tamil Nadu is concerned, with a view to improving the lot of the orphaned child, the Mother Teresa Memorial Financial Aid has been constituted. According to its constitution, the orphans are entitled to a sum of Rs.7,000 for their marriages. The EVR-Maniyammai Memorial Free Education Scheme has been implemented in Tamil Nadu and under that scheme a deserted or orphaned female child is given sewing machine, education facilities, etc., up to a sum of Rs.24,000. These are the salient features of the schemes which Tamil Nadu is following in respect of orphaned and destitute children. With respect, I urge on the Minister to consider these suggestions. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Mr. Javare Gowd. Unfortunately, you have only one minute.

SHRI H.K. JAVARE GOWDA (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, as far as this Bill is concerned, I would like to draw the attention of the Law Minister to the amendment suggested by Shri Ranganath Misra. If that is adopted, the problem is solved. There is only one word. What is that one word? In the definition clause you have specifically mentioned all the other things, but you have not defined who is an adoptive father or mother.

If you had defined that one word, according to me, the entire problem would have been solved. You have specifically defined the words "Board", "competent authority", "fit person", "local authority", etc. To give moral support to the juvenile and to safeguard the dignity and integrity of the juvenile, you have removed the word "court" and put "local authority". The whole intention is that. Sir, so far as adoption is concerned -- we are all practising advocates -- we know that the Courts are bound to interpret it in their own way. Now, in Section 41 (6), you have stated about single parents. If the single parent does not have any issue or any relative, then where would his/her property go? What is the legal position? To overcome this, I urge upon the concerned Minister as well as the Law Minister to kindly clarify it in the definition section. An adopted father has only a limited purpose, namely, adoption, care and protection, and he does not have any other right. Now, this matter also may be clarified. As regards the other matter, I congratulate the Minister; she has taken pains to bring in this legislation with a broad consensus. This is the need of the day because we are seeing a lot of children begging, and they are the means for some persons for getting income. Apart from that, we are also seeing in the Remand Homes that the children are not properly taken care of. Under these circumstances, it is essential to have this legislation, and it has to be passed. But the Law Minister should take this opportunity and make an amendment in the definition clause. Thank you, Sir.

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM (Tamil Nadu): Sir, until and unless Sections 14 and 15 are amended, there is no use having this Act. Our former Chief Justice, Shri Ranganath Misra, has suggested some amendments. As far as Section 41 of the present legislation is concerned, it says: "The Board may allow a child to be given in adoption to a single parent." Now, after the death of that parent, how can that child claim the property? The Bill also says: "Amendments shall be subject to the personal law of the adoptive parent." So, until and unless the legislation, which has been moved, is amended, there is no use having this Act. Hence I request the hon. Minister to make an amendment, so far as this provision is concerned.

श्री बाबी आज़ाद (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद उपसमाध्यक्ष महोदय। मैं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2000 को लाने के लिए मंत्री जी का स्वागत करते हुए इसका समर्थन करता हूँ। महोदय, हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि बालकों की सभी आवश्यकताएं पूरी की जाएं और उनके बुनियादी मानवीय अधिकारों को पूर्ण संरक्षण दिया जाए। यह दायित्व राज्य सरकार का है। किशोर बालकों को न्याय मिले इस बात को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 20 नवम्बर, 1989 को किशोर बालकों से संबंधित

कन्वेंशन को अंगीकार किया और खुशी की बात है कि हमारे देश ने भी इस कन्वेंशन का 11 दिसम्बर, 1992 को पूर्ण समर्थन किया।

महोदय, कोई भी माता-पिता अपने बच्चों को अनैतिक कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं करता है। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए या बंधुआ मजदूरी करने के लिए उत्साहित नहीं करता है, लेकिन उनकी मजबूरी के कारण बच्चे अनैतिकता के शिकार हो जाते हैं। स्थानीय पुलिस बच्चों का अनावश्यक रूप से उत्पीड़न करती है इस वजह से भी ज्यादातर बच्चे अनैतिक कार्य में लिप्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ गांवों में सामंतशाही व्यवस्था के शिकार बच्चे भी उत्पीड़न के शिकार होने के कारण अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। अतः मंत्री महोदया से मेरा निवेदन है कि इन सब कारणों को दूर करने के लिए विचार किया जाए और इन कारणों का निवारण किया जाए तो शायद अनैतिक कार्य करने वाले बालकों की संख्या में कमी आ सकती है। इस किशोर न्याय के लिए 50 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकारों का और पचास प्रतिशत हिस्सा केन्द्रीय सरकार का सुनिश्चित किया गया है। साथ ही साथ 11 करोड़ राज्यों के लिए और संघ राज्य के लिए एक करोड़ रुपए रखे गये हैं। मेरी राय में इतने बड़े देश के लिए यह धनराशि बहुत ही कम है। मैं मंत्री महोदया से अपील करना चाहता हूँ कि इस अनुपात को, केन्द्रीय शेयर को और बढ़ाना चाहिए ताकि उसी अनुपात में प्रांतीय शेयर बड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय मिले। महोदय, किशोरों को न्याय दिलाने में लगे लोग किशोरों का सुधार करने की जगह अपना ही सुधार करने लगते हैं जो अच्छी बात नहीं है। इन सारी बातों पर प्रतिबंध लगाने की प्रत्याशा में और किशोरों को पूर्ण न्याय मिलने की आशा में मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Madam, there is one thing. The hon. Member, Shri Ranganath Misraji, has suggested an amendment. There is one more alternative, perhaps. The expression 'Notwithstanding anything contained to the contrary in any other Act', could be a qualifying clause for your adoption, or, you may also consider the expression, 'Adoption under this Act will not be considered adoption under the personal law of the adoptive person'. If you can consider either of these two *via media*, it may, perhaps, obviate the possible legal wrangles that may take place, obviously, for property. Would you consider giving a reply?

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Sir, has everybody finished?

SHRI RAM JETHMALANI (Maharashtra): I wish to speak, Sir. And after that, the Minister can respond to what you have said.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Yes; of the three luminaries who were referred to by the earlier Chairman, I was one-quarter of them.

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I know that the time is very short. I will take the first ten seconds only to pay a compliment to the very

[20 December, 2000] RAJYA SABHA

enlightened Minister who has brought this very enlightened measure before the House and, I believe, this measure deserves the complete support of all sections of this House.

Now, Sir, there is an amendment which has been proposed by my friend, Shri Ranganath Misra. Sir, I am a little surprised that this amendment comes from a distinguished ex-Chief Justice of India. To subject all adoptions under this Act to the personal law of the parties is to retard the process of rehabilitation, to create endless complications and disputes, and it will end up the poor child in a court of law, rather than in a family which will rehabilitate him.

The original purpose of personal law adoption - I am talking particularly of Hindu Law - was wholly spiritual. The spiritual purpose that the Privy Council mentioned in Amrendra's case long, long ago was that there should be a male child available to offer 'pindas' to your departed ancestors, because, according to Manusmriti, there is no place in heaven for a sonless person. Therefore, that was the original purpose of adoption. Now the purpose of adoption under this Act is totally, totally different. It has nothing to do with religion. It has nothing to do with the 'pindas'. It has nothing to do with any spiritual rehabilitation of your ancestors. It has something to do with the physical, economic and social rehabilitation of the unfortunate child. Therefore, Sir, adoption under this Act to be subjected to the principles of an institution that is totally foreign to this, is to create endless complications. I must concede that this legal state of affairs leaves one question in a somewhat ambiguous State. Is the child adopted under the provisions of this statute a child for the purpose of the law of succession? It is true that this question is a question that is still doubtful and is not effectively answered. But I would rather leave this question unanswered today because if those magnificent persons with munificent intentions, who want to do social service, want to adopt a child and they want to so adopt the child so that he has also a right of inheritance, it is for them to take care. But if they don't want to give him rights of inheritance, or, they want to give him something less, they can disinherit the child by will. Therefore, that freedom to dispose of your property remains. But I will be very happy if the courts, hereafter, construe that an adopted child under this statute is also a child for the purposes of the law of inheritance. I concede, Sir, that this is ambiguous, but let us leave this ambiguous. Some day, some court will give to it a more beneficial interpretation. Sir, I think the idea being to prevent vagrancy, prevent

abuse, prevent abandonment ...*(Interruptions)*... I don't see why a person should not be able to adopt. ...*(Interruptions)*... I hate to speak about my first person singular. I have adopted a grand child who is a Muslim boy. Now, if you apply the personal law to all adoptions under this Act, you might create complications. The Hindu Law does not permit adoption of Muslim children. So, this is a secular measure which has been brought in. For the first time, it is an enlightened piece of secular legislation, and I am surprised that you want to revert back to the middle ages and subject it to the personal law. Therefore, Sir, I respectfully suggest to my friend, Shri Ranganath Misra to withdraw this amendment, and leave this in a state of measure. This, in fact, is one step in the direction of creating a Uniform Civil Code, though, Sir, I must make it very clear that I am wholly opposed to a Uniform Civil Code. I am for uniform justice in all laws. All laws require to be modified to produce justice, and this is one measure which does it; so, let us not complicate things for the poor child.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Thank you, Mr. Jethmalani. Now all the four legal luminaries have spoken and the square is complete, which requires to be answered. ...*(Interruptions)*... Nothing.

SHRI R. MARGABANDU: Sir, I want to speak for the clarification of Shri Ranganath Misra and the Law Minister. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): You have already spoken. ...*(Interruptions)*...

SHRI R. MARGABANDU: Sir, I may be permitted to speak for just one minute. With reference to the amendment, "provided that such adoption shall be subject to the personal law of the adopted parents. ...*(Interruptions)*... In respect of the personal law of a Hindu - it has been rightly pointed out ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): You have already made your point.

SHRI R. MARGABANDU: A person having a son, cannot adopt a son or a daughter. Now, if he adopts another son or daughter, that adoption becomes invalid. If that becomes invalid under the Hindu law, then he will not inherit any property. That is why Shri Thalavai Sundaram has suggested that unless sections 14 and 15 of the Hindu Succession Act are amended, giving power to inherit - as rightly said by Shri Ram Jethmalani - it will not serve the purpose. So, that should be taken care of.

[20 December, 2000] RAJYA SABHA

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU : Sir ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): No more discussion. Everybody had an opportunity. ...*(Interruptions)*... No interruptions will go on record. Now, the hon. Minister. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Sir, to begin with, I would like to thank the Law Minister, Shri Nariman, Shri Jethmalani, who is brilliant, as usual, Justice Misra and other legal luminaries who have applied their minds to it. I am happy that they have managed to clear most of the confusion that had existed. I thank all the hon. Members who have taken part in the discussion. Before I begin - I am going to keep my speech very brief because I would like the Law Minister to clarify whatever needs to be clarified. I want to say that when I became a Minister, the first thing I started was child line, which was a rescue service for all children on the road. We started it in nine cities, and we simply did this. We have a phone number - 1098. We said, any child that was being abused, sexually or otherwise, was being beaten, was being misused by the police, was begging, was simply tired of being on his own or of her own, could call this number which is toll-free and we could pick them up. We have picked up, in Mumbai alone, 1.5 lakh children; we have picked up 40,000 children in Delhi. We are now spreading it to 30 cities because from everywhere has this demand come. There are many, many children who, for no fault of their own, are street children, who did not ever know their parents, who grew up in gangs, who are abandoned, who were found in dustbins, who were found in gutters, who were taken from Bihar and thrown into Delhi when they were just two years old who have nobody; that is why we thought of this Bill as a secondary measure to child line. It has taken me two years. As explained yesterday, there is no legal luminary, there is no social worker, and there is no policeman of repute involved in the making of this Bill. I am not a legal person and I am going to say it in my own way.

The primary objective behind allowing adoption is to ensure the right of a child without a family, who may be abandoned or orphaned or destitute, to grow up in a congenial atmosphere and to see that it is not denied to him or her. When you talk about inheritance, what is my purpose? My purpose is not to incur the liabilities of the personal law nor confer the privileges of the personal law. It is really to let the adopted child get a home. It is that simple.

The Law Minister will clarify many things. He will tell you much better than me. All I know is that we have to get some way to get these children off the roads and into our minds and hearts. As we have become one billion people, I would say, out of that, 400 million would be completely powerless individuals, at the mercy of the system that they did not create. Let us not quibble over small things like 'a's, 'the's and grammatical errors.

I will sort them out, because I am as keen as you are in protecting them so that there are no loopholes. Tomorrow, somebody will come and will do even a better job than me. This is the best that I could possibly do.

To answer one by one, Mrs. Bharati Ray mentioned that the Bill had not gone into the causes of the destitution, neglect, etc. It is true. We have not gone into the causes. The causes-you and I know them well - are because of over-population, lack of care, lack of education, etc. My idea is not to go into the causes but to see whether I can deal with the consequences of those causes. Then, you also suggested on the punishment period of six months to three years. But let me explain it to you. All the offences against children have been made cognisable now, under clause 7, for the first time. Before this, they were not even recognised as offences. You could do whatever you want, to a child. So, we felt that these were good enough, to begin with. I would like to make them more stringent because it enrages every woman as to why a child should be taken advantage of.

Regarding Mrs. Dubey, about the guidelines to be provided, it may be pointed out that once the Bill is passed, model rules will be framed for enabling the States to make rules as well. Mrs. Dubey also mentioned that the Bill provides for all juveniles. The Bill provides for rehabilitation of juveniles, as an option.

Mrs. Raikar and others said that the Bill talks only of delinquents. No, it is not. The heading of the Bill is clear; and it is 'protection'. It is divided into two. One is for delinquents and the other is to give an option to children who are not delinquents, they are merely abandoned.

We have spent a lot of time arguing over adoption. There are many social options given here. Perhaps, we should look at those as well. I would be deeply grateful if this House would join in looking after the children by passing this Bill.

Thank you.

6.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): The question is:

That the Bill to consolidate and amend the law relating to juveniles in conflict with law and children in need of care and protection, by providing for proper care, protection and treatment by catering to their development needs, and by adopting a child-friendly approach in the adjudication and disposition of matters in the best interest of children and for their ultimate rehabilitation through various institutions established under this enactment, as passed by Lok Sabha be taken into consideration.

The Motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 40 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Clause 41. There is one amendment. Mr. Misra, are you moving?

SHRI RANGANATH MISRA: Sir, I do not propose to press my amendment in view of what the Chair observed and if that is considered. You made an observation at one point of time. I accept the solution that you have proposed. If it is available to there, then it will be all right.

Clause 41 was added to the Bill.

Clauses 42 to 70 were added to the Bill.

Clause 1, The Enacting Formula, Preamble and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

RAJYA SABHA [20 December, 2000]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): The House stands adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at three minutes past six of the clock, till eleven of the clock on Thursday, the 21st December, 2000.